राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 4

जुलाई - अगस्त 2007

आजादी के साठ वर्ष

60 years of Independence

1947 - 2007

1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ पर पुणे ॲकेडमी फॉर ॲडव्हान्सड् स्टडीज द्वारा निर्मित C D

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेश आयोजित छात्र संघ चुनाव – चुनौतियाँ एवं दिशा – राज्यस्तरीय परिसंवाद में उपस्थित अतिथि

यौन शिक्षा के विरोध में 14 जुलाई को दिल्ली में आयोजित विशाल सम्मेलन में बोलते हुये परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री अतुल कोठारी

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 30 अंक : 4, ● जुलाई-अगस्त, 2007

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

फोन : 011 – 27666019, 27662477
E-mail : chhatrashakti@yahoo.co.in
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

छात्रशक्ति

"राष्ट्रीय छात्रशक्ति" की ओर से सभी पाठकों एवं देशवासियों को *स्वतंत्रता दिवस* की हार्दिक शुभकामनाएँ।

विषय सूची

कविता : झाँसी की रानी 4

प्रमुख लेख

आत्मविश्लेषण की जरूरत 6

आजादी की पहली लड़ाई 8

आजादी के साठ साल, हमने क्या खोया और क्या पाया 10

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक : प्रस्ताव 12

मुलाकात

अ.भा.वि.प. अध्यक्ष, डा. रामनरेश सिंह 18

यौन शिक्षा :विरोध के प्रखर स्वर 20

यौन शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन – रिपोर्ट 22

परिचर्चा

व्यवस्था परिवर्तन में युवाओं की भूमिका 24

Yuva Vikas kendra: vision of a new diemension 26

परिषद् गतिविधियां 28

आह्वान

* क्या आप देश की वर्तमान दशा पर चिन्तित हैं?
* क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में छात्र–युवा ही सक्षम हैं?

यदि हां

* तो अपने क्षोभ को शब्द दीजिए और विश्वास कीजिए, आपमें क्षमता है कलम की नोंक से दुनिया का रुख बदलने की।
* अपने विचारों को साहित्य की किसी भी विधा में शब्द दें तथा राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 को प्रेषित करें।

" झाँसी की रानी "

- सुभद्रा कुमारी चौहान -

गतांक से आगे.....

रानी रोयी रनिवासो में, बेगम गम से थीं बेज़ार,
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार,
सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार,
नागपुर के ज़ेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार।
यों परदे की इज़्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान,
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान,
नाना धुंधूपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान,
बहिन छबीली ने रणचण्डी का कर दिया प्रकट आह्वान।
हुआ यज्ञ प्रारम्भ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी,
यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी,
झाँसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी,
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी,
जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम,
नाना धुंधूपंत, ताँत्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम,
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर, कुँवरसिंह, सैनिक अभिराम,
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम।
लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरबानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

इनकी गाथा छोड़, चले हम झाँसी के मैदानों में,
जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बड़ा जवानों में,
रानी ने तलवार खींच ली, हुया द्वन्द्व असमानों में।
ज़ख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

रानी बढ़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार,
घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार,
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार,
विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार।
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।।

विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी,
अबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी,
काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी,
युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
पर पीछे ह्यूरोज़ आ गया, हाय। घिरी अब रानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

तो भी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार,
किन्तु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार,
घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये अवार,
रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार–पर–वार।
घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी,
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी,
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी,
हमको जीवित करने आयी बन स्वतंत्रता–नारी थी,
दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।

जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनासी,
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फाँसी,
हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झाँसी।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी,
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। ■

संपादकीय

विष्वास से भरा है भारत

पूरा देश आजादी की साठवीं वर्षगांठ मना रहा है। हालांकि साठ वर्ष का कालखण्ड भारत जैसे सनातन राष्ट्र के लिए अधिक महत्व का नहीं है लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते आजादी की साठवीं वर्षगांठ मनाना हम सबके लिए गौरव का विषय है और वह भी ऐसे समय में जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में कहीं राजतंत्र है, तानाशाही है तो कहीं फौजी शासन। यदि आपातकाल के थोड़े से कालखण्ड को छोड़ दें तो भारत में लोकतंत्र निरंतर अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व के अनेक बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत में लोकतंत्र एक नई इबारत लिख रहा है और आजादी के 60 वर्षों में भारत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

पिछले साठ वर्षों में अपने देश में खासे बदलाव हुए हैं, जिनसे कभी हमारा सीना चौड़ा होता है तो वहीं हम अपनी नाकामियों पर शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। एक ओर देश विकास की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर व्यवस्था का विद्रूप आलम हमें खिझाता है।

अब भारत का विकास दर लगभग चीन के बराबर तक पहुंच गई है। हमारा निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी ऊंचाई पर है। डालर के मुकाबले रूपया मजबूत हो रहा है। हमारे बुनियादी ढांचा में भी तेजी से सुधार हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा डंका बज रहा है। सॉफ्टवेयर का निर्यात अरबों डालर तक पहुंच चुका है। तीन दशक पहले हमें अनाज आयात करना पड़ता था वहीं अब गोदामों में अनाज भरे पड़े हैं। अरबपतियों की संख्या दनादन बढ़ रही है। मोबाइल क्रांति के अनोखे चमत्कार हुए हैं। शेयर के दाम उछल रहे हैं। भारत के कॉल सेंटर विश्वभर में दबदबा कायम कर रहे हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसी भारत की बेटियों ने देश का नाम रौशन किया है। सानिया मिर्जा टेनिस की बुलंदियों को छू रही है। सचिन तेंदुलकर ने विश्व किकेट को एक नई पहचान दी है। आध्यात्मिक विभूतियां–मां अमृतानंदमयी,आसाराम बापू,मोरारी बापू, श्रीश्री रविशंकर, बाबा रामदेव जैसे अनगिनत संत–साध्वी विश्व को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। दुग्ध क्रांति का विस्तार इस कदर हुआ है कि आज हम सालाना करोड़ों लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं।

वहीं विकास की इस चकाचौंध में आज भी अनेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। गरीबी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, बालश्रम, भुखमरी, कुपोषण, किसानों की आत्महत्या, धर्मांतरण, घुसपैठ, अशिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, बढ़ता आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगे, बेलगाम महंगाई, बेहतर सड़क–बिजली–पानी के अभाव से देश की स्थिति भयावह हो रही है। उदारीकरण और वैश्वीकरण से आम आदमी को फायदा नहीं हुआ है, अलबत्ता कॉरपोरेट जगत जरूर फले–फूले हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70 प्रतिशत आबादी कृषि व्यवसाय के सहारे अपना जीवन गुजार रहे हैं लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 40 प्रतिशत किसान, किसानी छोड़ना चाहता है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2005–06 में घटकर 20 फीसदी रह गया। यह अजीब विडंबना है कि लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान मौत को गले लगाने पर मजबूर हो रहा है। हाल ही में देश ने देखा कि मजदूरों के हित का राग अलापने वाले माकपा–भाकपा ने किस तरह अपना हक मांग रहे किसानों पर बर्बर जुल्म ढाए। वर्तमान में राजनीति से लोगों का भरोसा उठ रहा है। पिछले 60 साल में 50 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया है। पूरे समाज की चिंता करने की बजाए सभी दलों में वोट–बैंक के चक्कर में मुस्लिम तुष्टिकरण की होड़ लगी है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो केन्द्र सरकार यौन शिक्षा के बहाने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार कर रही है। शिक्षा अब बाजार की वस्तु बन गई है। शुल्कों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। देश में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 32 हजार विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आजादी के 60 सालों के बाद देश की यह स्थिति चिंताजनक है। इस अंधकार के खिलाफ तमाम जनसंगठन और सामाजिक कार्यकर्ता मशाल थामे हुए हैं। भारत एक सनातन राष्ट्र है, विचारधारा है, दुनिया के लिए प्रकाश–स्तंभ है। विगत साठ वर्षों में हमने नेहरूवादी और समाजवादी मॉडल अपनाकर देखा। समाज के अंतिम आदमी तक विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई। अब सबको समझ में आने लगा है कि 2020 में समृद्धशाली भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम पाश्चात्य देशों का नकल छोड़कर अपनी ही तासीर के मुताबिक विकास प्रकिया को आगे बढ़ाएं। ■

आत्मविष्लेषण की जरूरत

- डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम -

(पूर्व राष्ट्रपति डा. कलाम के हैदराबाद में दिए गए भाषण का "उमाषंकर मिश्र" द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद)

हम अपनी सामर्थ्य और उपलब्धियों को ज़ाहिर करने में आखिर झिझकते क्यों होते हैं? हम एक महान देश के वासी हैं। हमारे देश को गौरव प्रदान करने वाली अनेक विस्मयकारी गाथाएं हैं, लेकिन हम खुद क्यों नहीं इस बात समझ पा रहे हैं!

- हम दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं।
- रिमोट सेन्सिंग सेटेलाईट के क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं।
- गेहूं उत्पादन में हमारा देश दूसरे स्थान पर है।
- दुनिया में चावल उत्पादकों में भी भारत का स्थान दूसरा है।

डा. सुदर्शन को देखो! जिन्होंने एक आदिवासी गांव को पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने का कार्य किया है। ऐसी लाखों उपलब्धियां हैं, लेकिन हमारा मीडिया केवल बुरा असर डालने वाले समाचारों, विफलताओं और विपदाओं के प्रस्तुतिकरण से पूरी तरह ग्रस्त है। एक समय मैं तेल अवीव में था और एक इस्रायली अखबार पढ़ रहा था। एक दिन पहले ही वहां विध्वंसक हमले एवं गोलाबारी हुई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। हमास इस हमले से बुरी तरह प्रभावित था। इतने पर भी अगले दिन के समाचार पत्र में हमलों के चित्रों की बजाय एक यहूदी व्यक्ति का चित्र प्रकाशित किया गया, जिसने 5 वर्षों के अपने अथक प्रयासों से मरुभूमि को पूरी तरह हरा भरा बना दिया था। इस तरह की विकट परिस्थितियों में पहले पन्ने पर प्रकाशित यह चित्र वास्तव में प्रेरणास्पद था। जबकि नरसंहार का रक्तरंजित विवरण, गोलाबारी इत्यादि की खबरों को अंदर के पृष्ठों पर अन्य समाचारों के साथ प्रकाशित किया गया था।

मैं हैदराबाद में जब इस भाषण को दे रहा था तो, 14 वर्षीय बच्ची मेरे पास ऑटोग्राफ लेने आई। मैने उससे पूछा– जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। उसका जवाब था कि – मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूं।" उस बच्ची के लिए आपको और मुझे मिलकर विकसित भारत का निर्माण करना है।

भारत में हमें अखबारों में बहुधा मृत्यु, बीमारी, आतंकवाद और अपराध जैसी खबरें ही प्रमुखता से पढ़ने को मिलती हैं। हमारी सोच इतनी नकारात्मक क्यों है? एक और सवाल– एक महान राष्ट्र होते हुए भी हम आखिर क्यों विदेशी वस्तुओं के आकर्षण से ग्रस्त हैं? टीवी हो, शर्ट या फिर तकनीक; हमें सब कुछ विदेशी ही चाहिए। "क्या हमें इस बात का कभी आभास नहीं होता कि आत्मसम्मान की प्राप्ति आत्मविश्वास से ही हो सकती है। मैं हैदराबाद में जब इस भाषण को दे रहा था तो, 14 वर्षीय बच्ची मेरे पास ऑटोग्राफ लेने आई। मैने उससे पूछा– जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उसका जवाब था कि – मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूं।" उस बच्ची के लिए आपको और मुझे मिलकर विकसित भारत का निर्माण करना है। आपको यह साबित करना होगा कि भारत कोई अल्प–विकसित देश नहीं; बल्कि इसका दर्जा कहीं ऊपर है।

आप कहते हैं कि हमारी सरकार अक्षम है, आप कहते हैं कि हमारे कानून बहुत पुराने हो चुके हैं, आप कहते हैं कि नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करते और रेलवे तो एक मजाक है, आप कहते हैं कि हमारी एयरलाईन्स सेवाएं विश्व में सबसे लचर हैं और डाक भी समय पर नहीं पहुंचती। ऐसे ही आप और भी बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि, आप इस तरह की समस्याओं में सुधार हेतु क्या करते हैं? सिंगापुर जाने वाले किसी व्यक्ति को उदाहरण के तौर पर लीजीए। मान लीजीए की वो आप ही हैं। आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आप खुद को विश्व के उत्कृष्ट हवाई अड्डे पर पायेंगे। सिंगापुर में आप न तो सड़क पर सिगरेट पीकर फेंकते हैं और न ही स्टोर्स में खाते हैं। आपको 5 बजे से 8 बजे के दौरान आर्कड रोड से गुजरने के लिए 5 डॉलर करीब 60 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेस्टोरेंट अथवा शॉपिंग

मॉल में अधिक समय तक बिना किसी जानकारी के रुके रहने पर पार्किंग स्थल पर आप अपना पार्किंग टिकट पंच करवाने के लिए खुद वापस स्वयं वापस आते हैं। रमजान के दौरान सार्वजनिक तौर पर क्या दुबई में आप कुछ खा सकते हैं? आप जेद्दाह में बिना सिर ढंके बाहर निकलने का साहस शायद ही करेंगे। अपनी एसटीडी और आईएसडी कॉल्स के बिल को किसी और के नाम करवाने के लिए किसी कर्मचारी को खरीदने की जुर्रत लंदन में आप नहीं कर सकते। वाशिंगटन में निर्धारित स्पीड से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाने के बाद आप पुलिस कर्मचारी को ये नहीं कहेंगे कि – "जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फलाने का बेटा हूँ।"

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप नारीयल के खोखे को यहां नहीं फेकेंगे। आप टोकियो की सड़कों पर पान खाकर क्यों नहीं थूकते? आप बोस्टन में जाली सर्टीफिकेट क्यों नहीं बनवा पाते??? इन सब वाक्यों में 'आप' हैं। ये आप ही हैं जो अन्य देशें में जाकर वहां के अनुकूल आचरण करने लगते हैं, लेकिन आप अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर पाते? जैसे ही आप भारत में वापस कदम रखते हैं, सड़कों पर कागज के टुकड़े और सिगरेट पीकर फेंकना शुरु कर देते हैं। अन्य देशें में एक अच्छे नागरिक सा आचरण आप अपने देश में क्यों नहीं कर सकते?

एक बार साक्षात्कार में मुम्बई के पूर्व म्युनिसिपल कमीश्नर श्री टिनायेकर ने एक गौर करने योग्य बात कही। उन्होंने कहा कि अमीर घरों के लोग अपने कुत्तों खुला छोड़ देते हैं, या फिर खुद टहलाने के लिए ले जाते हैं और बहतायत में यत्र तत्र सर्वत्र कुत्ता महाशय मल त्यागकर सड़क को गंदा कर देते हैं। फिर वही लोग खडंजों पर गंदगी होने की बात करते हैं और सम्बन्धित विभाग को दोषी ठहराते हैं। आखिर वे लोग विभागीय अधिकारियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? आखिर आप ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हैं। जापान और अमेरिका में प्रत्येक कुत्ते पालने वाले व्यक्ति को इस तरह की स्थिती में खुद सफाई करनी पड़ती है। क्या भारतीय नागरिक भी यहां ऐसा कर सकते हैं? हम एक सरकार का चयन करते हैं और सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम यह आस लगाकर बैठ जाते हैं कि अब सरकार बड़े लाड प्यार से हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगी, जबकि हमें कुछ नहीं करना होगा। हमारी अपेक्षा रहती है कि सरकार सफाई करवाएगी, लेकिन हम खुद गंदगी फैलाना नहीं बंद करते और न ही कभी सड़क पर पड़े किसी कागज के टुकड़े को ही कूड़ेदान में उठाकर डालते हैं। हम चाहते हैं कि रेलवे हमें एकदम साफ सुथरे बाथरूम उपलब्ध करवाए, लेकिन हमने यह कभी सीखने की जरूरत महसूस नहीं की, कि उपयुक्त तरीके से बाथरूम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हम महिलाओं पर होने वाले अपराधों का जमकर विरोध करते हैं, लेकिन अपने घर में वही सब करते हैं जिसका हम बाहर विरोध कर रहे होते हैं। यही पूरा सिस्टम है, जिसे हमको बदलना है।

अपने आप से पूछें कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं? और भारत को अमेरिका जैसे विकसित देशों की श्रेणी खड़ा करने के लिए जो भी बन पड़े करना चाहिए। भारत को हमारे जिस योगदान की जरूरत है, उसके लिए मिलकर कार्य करें।

इस सिस्टम में कौन सी बातें समाहित हैं? इसमें हमारा पड़ोस, अन्य परिवार, दूसरे शहर, समुदाय और सरकार को शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं और आप नहीं। जब भी कुछ सकारात्मक योगदान की सिस्टम को जरूरत होती है तो हम खुद आगे आने की बजाय आशा करते हैं कि कोई जादूगर आएगा और अपने जादुई हाथों से सब कुछ पलट कर रख देगा।

एक आलसी और कायर की तरह अपने डर से ग्रस्त होकर हम अमेरिका चले जाते हैं, वहां के सिस्टम में रह कर गौरवमयी धूप सेंकने के लिए। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित लगता है तो हम इंग्लैंड भाग जाते हैं। जब इंग्लैंड में रोजगार नहीं मिलता तो अगली खाड़ी देशों की ओर उड़ान भरते हैं। जब खाड़ी में युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं तो भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लिया जाए। हर व्यक्ति देश को गाली दे देता है, लेकिन सिस्टम को सुधारने की पहल अपने स्तर पर कोई नहीं करता। हमारा अन्तःकरण, हमारा विवेक, पैसे का गुलाम हो गया है।

प्यारे भारतवासियों, यह विचारणीय लेख आपसे आत्मविश्लेशण कर अन्तःकरण को प्रेरणादायी होगा। अमेरिकियों के लिए कहे गए जे.एफ. कैनेडी के शब्दों को मैं भारतीयों के संदर्भ में रखकर कहना चाहूंगा कि–

अपने आप से पूछें कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं? और भारत को अमेरिका जैसे विकसित देशों की श्रेणी खड़ा करने के लिए जो भी बन पड़े करना चाहिए। भारत को हमारे जिस योगदान की जरूरत है, उसके लिए मिलकर कार्य करें। ■

आजादी की पहली लड़ाई

—संजीव कुमार सिन्हा

1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष

सन् 1857 का स्वतंत्रता–संग्राम अंग्रेजी हुकूमत पर वह पहला करारा प्रहार था, जिसकी परिणति 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के रूप में हुई। वास्तव में, यह स्वतंत्रता संग्राम कई मायनों में भारतीय इतिहास का सुनहरा अध्याय है। इसे आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध बगावत के स्वर नहीं उठे, निश्चित रुप से फिरंगियों को भारतवासियों की ओर से छिटपुट प्रतिरोध तो अवश्य झेलना पड़ता था, लेकिन पहली बार, 1857 में गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए पूरा समाज एकजुट हो गया। इस विद्रोह के प्रमुख कर्णधार मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, अमर सिंह, तांत्या टोपे, बहादुरशाह जफर, मौलवी अहमद शाह, राव तुलाराम आदि थे। एक तरफ, आधुनिक शस्त्रों से लैस अंग्रेजों की सेना, सब तरह की सुविधाएं, उनकी 'फूट डालो–राज करो' की नीति। दूसरी तरफ, आम आदमी अपने ही बलबूते आधुनिक हथियारों के अभाव में भी, भाला, तीर–धनुष, लाठी और देशी बन्दूक लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध रणक्षेत्र में उतर पड़े। भारतीयों ने उस महाशक्ति से लोहा लिया, जिसकी विश्व भर में तूती बोलती थी और उस समय ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से टकराना, तबाही को आमंत्रण देने के बराबर था। इस संघर्ष में दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अवध आदि स्थानों में अंग्रेजों से खुले मुठभेड़ हुए, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। प्रमुख रूप से उत्तर भारत–उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में यह संग्राम फैला, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में लोग बगावत के लिए मैदान में आए। इस क्रांति के परिप्रेक्ष्य में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक साधनों के घोर अभाव के बावजूद लोगों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया।

क्रांति की चिंगारी

अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया था कि जब तक भारतीय अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, तब तक भारत पर पूर्णरुपेण आधिपत्य नहीं जमाया जा सकता, क्योंकि भारतीय समाज की एकता का मुख्य आधार राजनीतिक न होकर धर्म और संस्कृति हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी परम्परागत 'फूट डालो और राज करो' नीति के तहत सभी भारतवासियों को ईसाई बनाने की कुटिल चाल चली और हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की।

कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों ने 1 जनवरी, 1857 को सेना में 'एनफील्ड राइफल्स' इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस बन्दूक में प्रयोग होने वाले कारतूस की छर्रे गाय या सूअर की चर्बी से लिपटे रहते थे। बन्दूक में कारतूस भरने के पूर्व इसके छर्रों को मुंह से काटना होता था। इसको लेकर हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों में असंतोष के स्वर उभरने लगे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसकी अवहेलना करने वाले सैनिक को कोर्ट मार्शल करने का निर्देश दिया। अवहेलना करने वाले कई सैनिकों से वर्दी और हथियार वापस लेकर उन्हें अपमानित किया गया।

बरहामपुर के 19 एन.आई. के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके फलस्वरुप अनुशासनहीनता के आरोप में पूरी कम्पनी को भंग कर दिया गया। इसे लेकर सैनिकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का वातावरण बनने लगा। इनमें से ही मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इस तुगलकी फैसले के खिलाफ खुलकर विरोध किया और अंग्रेजों को सबक सिखाने का ठान लिया। 29 मार्च, 1857 ई को पांडे ने अपनी कम्पनी के दो अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। इसके बाद कई अंग्रेज सैनिक उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, उन पर भी उसने गोली चला दी। उन्होंने जमकर अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया लेकिन अन्ततः वे पकड़ लिए गए और 8 अप्रैल, 1857 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। बाद में ही 34वीं कम्पनी भी भंग कर दी गयी। इस कम्पनी के सैनिक मंगल पांडे की बहादुरी और शहादत के बारे में अपने क्षेत्रों की जनता के बीच चर्चा करने लगे। इसी तरह की घटना लखनऊ में भी घटी। 2 मई को 7वीं अवध रेजीमेंट के सैनिकों ने भी ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इस आरोप में कम्पनी भंग कर दी गई। मंगल पांडे ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर देशधर्म की रक्षा की। उनकी शहादत रंग लाई। इससे प्रेरणा पाकर सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। उसकी प्रतिध्वनि तुरन्त मेरठ में गूंजी।

6 मई, 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में

3 एल.सी. (घुड़सवार सैनिक टुकड़ी) की परेड में 90 भारतीय घुड़सवारों को चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग का आदेश हुआ। 5 को छोड़कर 85 ने दांत से कारतूसों को काटने से इनकार कर दिया। आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था पर धर्म का उतना ही पालन। आदेश के उल्लंघन में इन 85 सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल भेजने से पूर्व 9 मई को परेड ग्राउण्ड पर शेष सैनिकों को चेतावनी देने के लिए बुलाया गया। उनके समक्ष उन देश–धर्मभक्तों को पूरे अपमान के साथ हथकड़ियां पहनाकर जेल भेजा गया। 9 मई की ही रात में 10 मई के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया गया। 3 एल.सी. के कमांडर को यह भनक मिल गई कि 10 मई को रविवार है, ईसाइयों का गिरजाघरों में प्रार्थना का दिन। विद्रोह पैदल सैनिकों द्वारा प्रारंभ होगा फिर घुड़सवार सैनिक उनसे मिल जायेंगे। 10 मई, 1857 को मेरठ में सचमुच क्रांति का सूत्रपात हो गया। बंदी सैनिकों मुक्त करा लिया गया। हथियार लूट लिए गए। मेरठ में अंग्रेज सेना थोड़ी थी। मेरठ आजाद हो गया।

आग की लपटों की तरह फैल गई क्रांति

मेरठ के विप्लवियों के दिल्ली प्रवेश के साथ यहां के सैनिक नागरिक भी उनसे मिल गए। 82 वर्षीय बहादुरशाह जफर को हिन्दुस्तान का सम्राट घोषित किया गया और उसके नाम पर अंग्रेजों से घमासान शुरू हो गया। पहले दौर में क्रांतिकारियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया परन्तु अंग्रेज दिल्ली को वापस लेने पर कटिबद्ध हो गए। सितम्बर, 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया।

आगरा नगर में ऊपरी शांति रही पर उससे सटे क्षेत्रों से विप्लवी लपटें पश्चिमी संयुक्त प्रांत के रूहेलखण्ड इलाके में, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी आदि जनपदों को छूने लगी। इन इलाकों की मुक्ति होती जा रही थी, लखनऊ में 3 मई को क्रांति का धमाका हुआ फिर वहीं से वह मई के अंत में अवध रियासत को अपने प्रभाव में ले लेती है। नवाब वाजिदअली शाह के कलकत्ता निर्वाचन के बावजूद अवध के सभी वर्ग के लोगों ने क्रांति में भाग लिया– जनक्रांति का नजारा था। प्रशासक जान लारेंस की पक्की पहरेदारी के बावजूद पंजाब में विप्लव की घुसपैठ हो गई, विशेष रूप से उन छावनियों में जहां सिक्ख सैनिकों की संख्या कम थी या जहां पुरविया पलटने थीं यथा पेशावर, फिरोजपुर, रमदान, जालंधर, अजनाला आदि।

पंजाब की तुलना में आज के हरियाणा के ग्रामीण अंचल के किसानों ने क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनमें रेवाड़ी के जमींदार राव तुलाराम व राव कृष्ण गोपाल, मेवाती सरदार अली हसन, समद खां, झज्झर के नवाब अब्दुर्रहमान, वल्लभगढ़ के नाहर सिंह, फरूखनगर के नवाब फौजदार खां ने छिटपुट विद्रोह किया।

क्रांति की अग्निशिखा दक्षिण भारत में निजाम के हैदराबाद रियासत तक पहुंची, इधर के बड़े नवाब और राजा बाहरी तौर पर सरकार के प्रति वफादार रहे पर अंदर से भी उनमें साहस की कमी थी। फिर भी देशी पलटन और जनता ने युद्ध में भाग लिया। हैदराबाद के जोतपुर, कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, धार, जबलपुर, खानदेश, पूना, बाम्बे आदि में स्वाधीनता युद्ध ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई।

इस क्रांति की मशाल बिहार में भी जली। यहां संघर्ष को नेतृत्व दिया जगदीशपुर रियासत के कुंवरसिंह और उनके भाई अमर सिंह ने। संघर्ष में जनता की भागीदारी ने हुकूमत को परेशानी में डाल दिया था। स्मरणीय है कि युद्ध के दौरान अनेक क्षेत्रों रियासतों में ब्रिटिश राज का शामियाना उखड़ गया था। एक बार तो दिल्ली से बनारस तक ग्रेडट्रंक रोड़ आजाद था।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सितम्बर–अक्टूबर 1857 में झांसी पर अपना पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन उनका कब्जा महज छह महिने तक रहा। आखिरी विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर इलाके में दबा दिया। 8 जुलाई 1858 को एक शांति संधि हुई और यह विद्रोह अंतिम रुप से खत्म हो गया।

क्रांति की उपलब्धियां

कुछ ब्रिटीश और वामपंथी इतिहासकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मात्र 'सिपाही विद्रोह' कहकर इसकी आलोचना करते है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह सही है कि सैनिकों ने इस लड़ाई का बिगुल बजाया लेकिन इसके साथ–साथ किसान, मजदूर, महिलाएं भी संगठित होकर रणभूमि में कूद पड़े थे। 1857 का युद्ध राष्ट्रीय था। इसका राष्ट्रीयता की दृष्टि से सबसे सुखद परिणाम सामने आया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। मराठों ने बहादुरशाह को सम्राट और मुसलमानों ने नानासाहब को पेशवा की मान्यता दी।

सन् 1908 ई. में प्रख्यात क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी चिंतक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की शौर्य–गाथा को 'वार ऑफ इंडिपेंडेंस' नामक ग्रंथ में लिखकर इसे स्वाधीनता युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रस्तुत किया। उनका भी मानना था, '1857 का विद्रोह केवल सैनिकों का बलवा नहीं था, अपितु यह भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रथम प्रयास था।' सावरकर की इस पुस्तक ने क्रांतिकारियों को राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। ■

आजादी के साठ साल, हमने क्या खोया और क्या पाया?

• देवेन्द्र स्वरूप

आजादी के इन साठ सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया यह जानने के लिए आजादी से पहले के सपनों को जानना होगा, सपनों को जानने के लिए प्रेरणाश्रोतों को ढूंढ़ना होगा, उन प्रेरणा –श्रोतों में सर्वप्रथम नाम गांधीजी का आता है। क्योंकि गांधीजी ने ही स्वतंत्रता आंदोलन को देशव्यापी जनांदोलन का रूप दिया। उनके 1920–30 के सत्याग्रह के माध्यम से जो नेतृत्व उभर कर सामने आया, उसे ही सन् 1947 के स्वाधीन भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों को साकार रूप देने का दायित्व प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य तीन धाराएं थीं, एक गांधी प्राणित धारा थी, दूसरी समाजवादी विचार से अनुप्राणित धारा थी और तीसरी सशस्त्र क्रांति की धारा थी। सशस्त्र क्रांति की धारा के सामने तो ब्रिटिश क्रांति के समाप्ती के आगे का चित्र स्पष्ट नहीं था। चिन्तन भी नहीं था। जबकि कांग्रेस के भीतर गांधीवाद और समाजवाद के बीच में वैचारिक बहस थी। यह बहस हमें 1945 में गांधी–नेहरू पत्राचार में नजर आता है। समाजवादी धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि जवाहर लाल नेहरू ने कई जगह इस बात को लिखा है कि भारतीय समाज को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदान देने की प्रेरणा केवल महात्मा गांधी दे सकते हैं। सब समाजवादी मिलकर भी नहीं। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के दर्शन और सपने के वास्तविक प्रणेता गांधी जी थे। समाजवादी नहीं।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ती के पश्चात सन् 1945 में यह दिखाई देने लगा था कि भारत की स्वतंत्रता निकट भविष्य में अवश्यंभावी है।

यह इतिहास का संयोग है कि गांधी जी हमको स्वतंत्रता के प्रवेश द्वार के भीतर पहुंचाकर चले गए और स्वाधीन भारत का शिल्पकार बनने का सुअवसर नेहरूजी को प्राप्त हुआ। पिछले 60 वर्षों में स्वतंत्रता आन्दोलन से भटका हुआ भारत नेहरूजी के सपनों का भारत है। गांधी के सपनों का भारत नहीं।

सन् 1945 के पत्राचार में गांधीजी ने यह सवाल उठाया कि तुम को मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि भारत की जनता यह जाने कि भावी भारत का तुम्हारा चित्र क्या है, जहां तक मेरा संबंध है, मैं आज भी 38 सालों के अनुभवों के बाद भी 1909 में हिन्द स्वराज में प्रस्तुत चित्र पर अटल हूं। मेरी दृष्टि में भारत का रास्ता बाकि दुनियां से अलग होगा। भारत शहरों में नहीं गांवों में रहेगा। महलों में नहीं कुटियों में रहेगा। गांधीजी ने यह भी लिखा कि यह संभव है, पश्चिम की मशीनी सभ्यता की

चकाचौंध से आकृष्ट होकर भारत भी भौंरे की तरह उसके चारों ओर मंडरा कर आत्मनाश कर ले। लेकिन मेरा धर्म है कि मैं चेतावनी दूं और मैं उसी धर्म का पालन करूं। नेहरूजी ने उत्तर में हिन्द स्वराज द्वारा प्रस्तुत चित्र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में जीवन जड़ है, भावी भारत इस जड़ता से बाहर निकलकर पश्चिम की गतिमान और औद्योगिक रास्ते पर भी बढ़ेगा। इन दो दृष्टियों का अंतर इस पत्राचार में स्पष्ट है। यह इतिहास का संयोग है कि गांधी जी हमको स्वतंत्रता के प्रवेश द्वार के भीतर पहुंचाकर चले गए और स्वाधीन भारत का शिल्पकार बनने का सुअवसर नेहरूजी को प्राप्त हुआ। पिछले 60 वर्षों में स्वतंत्रता आन्दोलन से भटका हुआ भारत नेहरूजी के सपनों का भारत है। गांधी के सपनों का भारत नहीं। हम एक नैतिक, लंबी सशक्त सम्मानित राष्ट्रजीवन की रक्षा करने वाले राष्ट्र के

बजाय, एक हिंसक, कामुकरुख्क, अनैतिक, उच्छृंखल, संकीर्ण निष्ठाओं में विभाजित, परमुखापेक्षी, सम्मानशून्य, भ्रष्टाचार में डूबे राष्ट्र के रुप में देखे जाते हैं। संसार के सर्वाधिक भ्रष्ट और विखंडित राष्ट्रों में हमारी गणना होती है। जिस आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के विनाशकारी प्रभावों को लेकर संपूर्ण विश्व में बहस चल रही है। जिसके कारण पर्यावरण का तेजी से संरक्षण हो रहा है। उस सम्यता के अंधाधुंध विस्तार को ही हम प्रगति मान रहे हैं। गांव–गांव में व्यक्ति–व्यक्ति तक मोबाइल पहुंचाने के आंकड़े फेंके जा रहे हैं। पर गेहूं और आटा जैसी मुलभूत आवश्यकताएं हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने की समाधि पर पंजाब से लेकर दक्षिण तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम परंपरा से प्राप्त विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर खोमचे–ठेले वालों और खुदरा व्यापारियों को बेरोजगार कर सब तरफ पूंजीपतियों का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। आर्थिक विषमता को बढ़ा रहे हैं। ऊंची–ऊंची अट्टालिकाएं, पंचसितारा होटल, लंबी–लंबी कारें इन्हीं को हम प्रगति के मानक कह रहे हैं। हमारा संपूर्ण मीडिया हिंसा, बालात्कार और लूट जैसे अपराधों के समाचारों से भरा होता है। मानवीय संवेदनाएं जैसे मर चुकी हैं। पुत्र द्वारा पिता की, पत्नी द्वारा पति की हत्याओं के समाचार आम बन गए हैं। पूरा वातावरण उच्छृंखल सेक्स की चर्चा से भरा हुआ है।

स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान जो राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ था, अखिल भारतीय राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत नेतृत्व खड़ा हुआ था। वह अब पूरी तरह तीरोहित हो चुका है। व्यक्तिगत् राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं, जाति, क्षेत्र और पंथ की संकीर्ण निष्ठाओं पर आधारित छोटे–छोटे अनेक दलों को खड़ा करने में लोकतंत्र की चर्चा के बावजूद अधिकांश राजनैतिक दल व्यक्ति या वंश केन्द्रित हैं। राजनीति में धनशक्ति, डंडाशक्ति के प्रयोग को मानो मान्यता प्राप्त हो गई हो। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर किसी एक दल के पूर्ण बहुमत में आने की संभावना धूमिल हो गई है। इस अवसरवादी सत्तालोलुप, संकीर्णतावादी राजनैतिक विध्वंश को लोकतंत्र के पुष्पीकरण का नाम दिया जा रहा है। आधुनिक मशीनी सभ्यता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा से विभूषित युवा वर्ग नौकरियों की खोज में बड़ी संख्या में विदेश जा रहा है। विदेशों की सेवाओं की पूर्ति के लिए भारत काल सेन्टरों का घर बनता जा रहा है। यह काल सेन्टर देश के लिए कुछ उत्पादित नहीं करते। वहां एक अजीब प्रकार की सभ्यता विकसित हो रही है। भारत की मिट्टी से जुड़ा ग्रामीण परीवेश पला युवक बेरोजगारी का शिकार है। हमारी संपूर्ण राजनीति वोट गणित का शिकार बन गई है और इस गणित के कारण भारत में अल्पसंख्यक वाद, सैकुलरिज्म, राष्ट्रीयता आदि शब्दों की नई–नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। राष्ट्रवाद अब संप्रदायवाद बन गया है। पृथकतावाद और आतंकवाद को सैकुलरिज्म का रक्षा कवच प्राप्त हो गया है। 60 के इस चित्र को हम क्या नाम दें? यह हमको कहां पहुंचाएगा? सत्ता दलीय राजनीति के बाहर सम्पूर्ण राष्ट्रजीवन नीष्क्रिय और नीर्जीव है। बौद्धीक और सांस्कृतिक धरातल पर नवजागरण के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश फिर से गांधी जैसे व्यक्तित्व की प्रतिक्षा कर रहा है। जो जनमानस में सुप्त सांस्कृतिक चेतना को उदबुद्ध कर एक नए विशाल जनआंदोलन का सृजन कर सके।

व्यक्तिगत् राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं, जाति, क्षेत्र और पंथ की संकीर्ण निश्ठाओं पर आधारित छोटे–छोटे अनेक दलों को खड़ा करने में लोकतंत्र की चर्चा के बावजूद अधिकांश राजनैतिक दल व्यक्ति या वंश केन्द्रित हैं। राजनीति में धनशक्ति, डंडाशक्ति के प्रयोग को मानो मान्यता प्राप्त हो गई हो। अब अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर किसी एक दल के पूर्ण बहुमत में आने की संभावना धूमिल हो गई है।

(यह लेख वरिष्ठ पत्रकार, चिन्तक एवं स्तम्भकार श्री.देवेन्द्र स्वरूप से आशीष कुमार 'अंशु' की बातचीत पर आधारित है)।

■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव–3 वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने शासन के 3 वर्ष पूरे कर लिये है। शैक्षिक परिदृश्य में केन्द्र सरकार का प्रदर्शन अत्यन्त निराशाजनक रहा है एवम् वह दिशाहीन हो गयी है। यहां तक कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वायत्तता सवालों के घेरे में है। संप्रग सरकार सदैव आम आदमी की बात करती है किन्तु उसके द्वारा क्रियान्वित शिक्षा के क्षेत्र की नीतियां एंव निर्णय जनसामान्य के हितों के विरोधी है। अभाविप की रा.का.प. यह अनुभव करती है कि यह नीतियां शिक्षा के व्यापारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं अल्पसंख्यकवाद को प्रोत्साहित करती है।

केन्द्र सरकार की नीतियों से देश में शिक्षा के व्यापारिकण को प्रोत्साहन का एक अप्रतिम उदाहरण आई.आई.एम. संस्थानों में शुल्क वृद्धि है। एक ओर जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भागीदारी निरंतर कम होती जा रही हैं वही सरकार ने स्ववित्तपोषित गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कई बार प्रवेश एवं शुल्क संरचना के नियमन हेतु चर्चा की एवं इस हेतु केन्द्रीय कानून का प्रारूप तैयार करके सभी राज्य सरकारों को भी भेजा, इस बात को दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस दिशा में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। निजी विश्वविद्यालय पर विधेयक तैयार किया, किन्तु इसको कानून बनाने का अथवा संसद में चर्चा हेतु रखने का कोई प्रयास नहीं किया। अभाविप संप्रग सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्री की निष्क्रियता की कडे शब्दों में निन्दा करती है जो गरीब एवं प्रतिभाशाली छात्रों के हितों को प्रभावित करती है।

शिक्षा की नीतियों के संदर्भ में केन्द्र सरकार में स्पष्ट दिशा का अभाव है। विभिन्न मंत्रालय एवं समितियां विभिन्न दिशाओं में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रधानमंत्री के अधीन कार्य कर रहा है, जिसने शिक्षा पर एक प्रतिवेदन तैया किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने "उच्च शिक्षा–गैट्स एवं इसके अवसर पर एक परामर्ष पत्र तैयार किया है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी शिक्षा प्रदाता पर एक विधेयक तैयार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार मे न तो मंत्रालयों में कोई समन्वय है और न ही उच्च शिक्षा की नीतियों में इसके पास कोई दिशा है। अभाविप कि रा.का. प. का यह मानना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में ऐसा दिशाहीन दृष्टिकोण राष्ट्र हित में नहीं है। तथा इस हेतु यह बदले वैश्विक परिदृष्य मे उच्च शिक्षा पर नये सिरे से एक संप्रग नीति बनाने की माँग करती है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह एक उच्चपदस्थ आयोग है। स्वयं आयोग के अध्यक्ष के शब्दों में यह आयोग भारत के प्रधानमंत्री की एक उच्चस्तरीय सलाहकार संस्था के रूप में गठित हुआ है और उसे नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुधारो के निर्देशन का अधिकार सौंपा गया है। किन्तु दुर्भाग्य से उसे प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुधारों के निर्देशन के अधिकार के महत्व से उसकी संस्तुतियां मेल नही खाती।

प्रथम दृष्टया ज्ञान आयोग की संस्तुतियों में कुछ सकारात्मक बिन्दु है जैसे शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढावा देना वर्तमान विश्वविद्यालयों में सुधार शिक्षा मे गुणवत्ता को बढ़ावा देना, सभी योग्य छात्रों हेतु शिक्षा की सुलभता सुनिनिष्चत करना पिछड़े एवं शोषित वर्गो के छात्रों के संदर्भ में सकारात्मक कार्य । किन्तु ठीक से विष्लेशण करने पर पता चलता है कि ये सारे बिन्दु पहले गठित आयोगों की संस्तुतियो में उल्लिखित हुये है लेकिन उनका आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। ऊपर से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस संदर्भ में कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है।

अनेक अन्य बिन्दु भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ में विचारणीय है। इस आयोग ने अपनी गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं किया है शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर देशभर के शिक्षाविद, छात्र संगठनों, शिक्षक संगठनों आदि से कोई चर्चा नहीं की गयी। कुछ गिने चुने लोगों के मतों को ही लिया गया । यहाँ तक कि स्वयं आयोग के सदस्य में संस्तुतियों को लेकर मतभिन्नता रही है। आयोग से त्यागपत्र देकर अपना प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद यह माँग करती है कि डॉ0 पी.एन. भार्गव के इस प्रतिवेदन को भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाईट पर जारी किया जाये।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनेक अनुशंसाये भी विरोधाभासी है। पहले तो आयोग उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधिकार को बांटने की बात कहता है, बाद में स्वयं एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (IRAHE) की बात

कहता है। इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद ने पहले ही समग्र दृष्टिकोण रखने वाला (प्राथमिक शिक्षा से शोध तक) स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की मौंग की है। आयोग द्वारा प्रस्तावित संस्थानों की बहुलता अन्याय जटिलताओं को जन्म देगी। शिक्षा के क्षेत्र मे निजीकरण के नाम पर कार्पोरिट क्षेत्र की सहभागिता शिक्षा में बाजारीकरण की प्रवृति को पुष्ट करेगी जो भारतीय शिक्षा की मूल भावना के विपरीत है।

संप्रग सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिये अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की नीति पर निरन्तर अग्रसर है, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी। संविधान के 93 वे संशोधन से जिसमें निजी संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को बाहर रखना निंदनीय हैं। अभाविप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग की रचना एवं उसमें राज्य सरकार की स्वयात्तता को नकारकर उसी में असीमित अधिकार निहित करने का पुरजोर विरोध करती है। अभाविप की रा.का.प. मांग करती है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग अविलंब भंग किया जाये।

अभाविप की रा.का.प. शिक्षा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की (FDI) अनुमति के संप्रग सरकार के निर्णय का विरोध करती है। प्रत्यक्ष विदशी निवेश के प्रारूप के स्वरूप से स्पष्ट होता है कि यह सारी प्रक्रिया व्यापारिक समझौतों के अधीन होगी। हमारा यह मानना है कि शिक्षा व्यापार समझौतों अर्थात गेट्स के अंतर्गत नहीं लायी जानी चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवश की अनुमति से बिना औपचारिक वार्ता के गेट्स समझौते के प्रावधानों को स्वीकार करने की अनिवार्यता होगी। अभाविप इसे राष्ट्रीय एवं शैक्षिक समुदाय के हितों के लिये विनाशकारी मानती है।

जहाँ तक विद्यालयों मे यौन शिक्षा का प्रश्न है अभाविप इसकी मूल संकल्पना का ही तीव्र विरोध करती है विस्तृत यौन शिक्षा की मूल संकल्पना ही पाश्चात्य है। एच.आई.वी.–एड्स पर जागरण लाने के नाम पर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर यौन शिक्षा को सम्मिलित करना बुद्धीमत्तापूर्ण कदम नहीं है। यूनीसेफ–मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपलब्ध घृणित साहित्य छात्रों को पढाने योग्य नहीं है, यहां तक कि अध्यापक भी इन पाठों की छात्रों से चर्चा करते समय लज्जा का अनुभव करते हे। विदेश का अन्धानुकरण एवं अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के दबाव में केन्द्र सरकार एवं सी.बी.एस.ई. अपने देश के सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों तथा परिवार व्यवस्था के साथ खिलवाड कर रहे है। अभाविप अनुभव करती है की इसके पीछे बाजारी शक्तियों का एक अंतरराष्ट्रीय षंडयंत्र है, जिससे अपने देश का सांस्कृतिक ताना–बाना नष्ट होगा। इसलिये अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग करती है कि देश में यौन शिक्षा के स्थान पर नैतिक एवं संस्कार देने वाली शिक्षा लागू की जाएं।

अभाविप की कार्यकारी परिषद उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बाद भी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश एवं शुल्क–निर्धारण की समस्या के बने रहने पर गंभीर चिंता प्रकट करती है। इन मुद्दों का विभिन्न राज्यों में उचित समाधान नही हुआ है। उच्चतम न्यायालय के इस पर उचित कानून बनाने के सुझाव के बाद भी केन्द्र एवं राज्यों की सरकार इस दिशा से कानून बनाने की पहल की है उसी प्रकार अभाविप केन्द्र एव अन्य राज्य सरकारों से भी आग्रह करती है कि वे एक कानून बनाये जो प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण के मुद्दों का समाधान करे जिससे व्यवसायिक शिक्षा में बनी अनिष्चिता एवं छात्रों का शोषण समाप्त हो सके।

अभाविप उच्चतम न्यायालय के शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग पर रोक हेतु दिये गये निर्णय का स्वागत करती है। अभाविप राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालयों से मांग करती है कि डॉ. आर.के. राघवन समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये सभी शैक्षिक संस्थानों में रैगिग विरोधी समितियों का गठन किया जाये।

अभाविप की रा.का.प. शिक्षा बचाओं आंदोलन समिति के उस प्रयास की प्रशंसा करती है जिसमें उसने सप्रंग सरकार के शासन में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों में की गयी तथ्यपरक त्रुटियों एवं विकृतियों को न केवल दूर करवाया अपितु उसके सतत एवं सजग प्रयास से अन्यान्य पाठयक्रम संबंधी सुधारों में भी सफलता मिली। ■

प्रस्ताव–4

केन्द्र सरकार की समझौतावादी नीति देश के लिए घातक

राष्ट्र का वर्तमान परिदृश्य अत्यंत चिंताजनक है। विगत दिनों में हुई घटनायें राष्ट्र की एकता, अखण्डता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। सीमाओं की असुरक्षा और घुसपैठ के कारण आतंकवादी भय मुक्त होकर बम विस्फोट तथा आम नागरिकों की हत्याएं कर रहे है, किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढी है देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई व आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी ने आम आदमी की कमर तोड दी है। एक ओर बेरोजगार युवकों की संख्या लगातार बढती जा रही है तो दूसरी ओर वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा राजनीति के तहत देश में अल्पसंख्यकवाद को बढावा दिया जा रहा है। भारतीय

संस्कृति और आस्था के मान बिंदुओं पर लगातार चोट हो रही है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द सरकार की राष्ट्रीय हितों पर समझौतावादी नीति को देश के लिए घातक मानते हुए उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।

वर्तमान केन्द्र सरकार की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के चलते न केवल कृषि क्षेत्र की लगातार घोर उपेक्षा हो रही है वरन् किसानों की हालत भी निरन्तर दयनीय हो रही है। शोध संस्था इण्डिक्स एनालिटिक्स ने 2005–06 में जो आंकड़े प्रस्तुत किये उससे कृषि अर्थव्यवस्था की एक भयावह तस्वीर उभरती है। देश में गेहूं के आयात के बाद आज दालों, खाद्य तेलों और यहां तक की दूध का आयात करने की मजबूरी है। खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य मानों ओझल होता जा रहा है। कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य न लि पाने के कारण किसान कर्ज के बोझ में डूबता जा रहा है। लगातार सरकार से हो रही उपेक्षा के चलते सन् 1995 से 2006 के बीच देश में लगभग 106000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। इस स्थिति के कारण, आर्थिक सुधारों के प्रवर्तक, प्रधानमंत्री को भी स्वीकारना पड़ा कि आर्थिक सुधारों से कृषि की उपेक्षा हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री की यह स्वीकारोक्ति केवल भाषण तक ही समिति रही है। देश में विशेश आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाने के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण करना एक ज्वलंत उदाहरण है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से मांग करती है कि सेज के लिए उपजाउ भूमि का अधिग्रहण नही किया जाए तथा सेज की नीति की पुनः समीक्षा करते हुए इसे हमारे देश की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बनाते हुए कृषि क्षेत्र में समग्र सुधारों के लिए ठोस रणनीति बनाकर उसे शीघ्र लागू करें।

भारत का व्यापार लघु एवं मध्यमवर्गीय व्यापारियों द्वारा नियोजित किया जाता रहा है। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के आने से लघु एवं मध्यमवर्गीय व्यापारियों को बेरोजगार तथा आत्महत्या की ओर धकेलना होगा। कृषि उत्पादों का वायदा व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कृत्रिम अभाव के कारण बढ़ती जा रही मंहगाई आम आदमी के दुःखों को बढ़ा रही है। अभाविप की यह कार्यकारी परिषद खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश का धोर विरोध करती है तथा सरकार से मांग करती है कि तुंरत मंहगाई पर रोक लगाये।

आतंकवाद एवं अलगाववाद के संदर्भ में केन्द्र सरकार की ढुल–मुल नीति के कारण आतंकवादियों एवं अलगाववादियों के हौसले लगातार बढ़ रहे है। परिणामस्वरूप गुवाहाटी में उल्फा द्वारा करायी घटनाएं, हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम विस्फोट, गोरखपुर मे श्रृखलाबद्ध विस्फोट, फैजाबाद में विस्फोटकों का मिलना ऐसी कई घटनाएं हुई है। गत दिनों घटी आतंकवादी घटनाओं के तार बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े होने से सिद्ध होता है कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पोशित करने वाले देश के रूप में उभरा है। संसद पर आतंकी हमले के आरोपी अफजल की फांसी की सजा पर सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय न लेने एवं आतंकवादियों से निपटने की कोई ठोस रणनीति न होने से सरकार की आवाज कमजोर और असरहीन हुई है। आतंकवादियों की शरणस्थली और उनको पोशित करने वाले पाकिस्तान एंव बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल ठण्डी है। परिणामतः जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में प्रतिबंधित संगठनों के झण्ड़े लहराये एवं पाकिस्तान के पक्ष में नारे बाजी करते हुए आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ विष वमन किया है। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का मानना है कि आंतकवाद एवं अलगाववाद के समर्थकों के साथ सौदेबाजी के घातक परिणाम होंगे। कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बढते दुस्साहस का अहम कारण उनके प्रति जरूरत से ज्यादा नरमी बरतना तथा उन्हें अनावष्यक अहमियत प्रदान करना है।

संप्रग सरकार द्वारा कश्मीर पर हुए दो गोल मंज सम्मेलन से कश्मीर के भारत में विलय जैसे सवाल फिर से जिंदा हुआ है। सरकार ने कश्मीर में मानवाधिकार और भारत – कश्मीर सम्बन्धों की सवैधानिक स्थिति जैसे विषयों पर अध्ययन दल बना दिये है। जम्मू कश्मीर से सेना की तैनाती के बावजूद आंतकवादी संगठन आम नागरिकों की हत्या तथा उन्हें आतंकित करने में सफल हो रहे है। ऐसे में मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा जम्मू काश्मीर से सेना वापस बुलाने तथा आर्म्ड फोर्सेज (स्पेषल पावर) एक्ट को निरस्त करने की मांग करना तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय हेतु एक समिति का गठन करना देष की एकता, अखण्डता, संप्रभुता एवं सैनिकों के मनोबल के साथ भयंकर खिलवाड है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड करने की कड़े शब्दों में निंदा करती है। अभाविप केन्द्र सरकार को आगाह करती है कि आंतकवाद को समाप्त करने का उद्देश्य पूरा नही होने तक सेना हटाने जैसे मुद्दे पर कोई बातचीत न करें एवम् राष्ट्र विरोधी किसी भी मांग के सामने घुटने न टेके।

पिछले दिनों नक्सली हिंसा के तहत देश भर में घटी घटनाएं हमारी आतंरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। गत 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस शिविर पर

हमला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सुनील महतो की दिन दहाडे की गई हत्या, बोकारों जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट मे 13 पुलिस कर्मियों की मौत, इत्यादि घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि नक्सलवादियों के हौसले बुलंद है। पिछले तीन महीने में नक्सलियों द्वारा 395 घटनाओं को अंजाम दिया गया 209 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। गृह मंत्रालय के खुफिया सूत्रों के अनुसार दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब जैसे प्रान्त भी नक्सलियों के निशाने पर आ गए है।

अभाविप की यह कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से मांग करती है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए राजनीति से ऊपर उठकर संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक समन्वित रणनीति बनाकर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा बलों को तैनात कर प्रभावित क्षेत्रों में एक साझा अभियान चलाया जाए।

पिछले दिनों समाचार पत्रों में छपी खबर की चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में 20 किमी. अंदर तक कब्जा कर लिया है, गंभीर चिंता का विषय है। अभाविप की कार्यकारी परिषद भारत सरकार से मांग करती है कि इस क्षेत्र को चीनी कब्जे से वापस छुडाने के लिये आवश्यक कदम उठाये तथा चीन को स्पष्ट संकेत दे कि भारत अपनी सीमाओं में किसी तरह की घुसपैठ बर्दाशत नहीं करेगा।

केन्द्र की संप्रग सरकार द्वारा सच्चर समिति की आड में अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ देने के लिए कार्यबल का गठन करना तथा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सरकार में हर स्तर पर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास का आश्वासन देना वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यह शासन के बुनियादी सिद्धांतों तथा देश के संविधान में मजहब के आधार पर भेद भाव न करने की भावना के खिलाफ है। अभाविप की इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का मानना है कि अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक कौन इसको परिभाषित किया जाए। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कि उत्तर प्रदेश मे मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इस पर देशव्यपी बहस चलाने की आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सेतु समुद्रम नहर परियोजना, राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत कर भारतीय संस्कृति के मान बिन्दुओं को ध्वस्त करने वाली, भू–पर्यावरण विरोधी, अवैज्ञानिक तथा लाखों लोगों का रोजगार समाप्त करने वाली अत्यंत संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। क्योंकि यह भारत और श्रीलंका के बीच विद्यमान, मन्नार खाडी के ऐतिहासिक जल डमरूमध्य, पर दोनों देशों के ऐतिहासिक अधिकार है, को नकारते हुए अमेरिका वहां घुसना चाह रहा है, यह बात देश की तटीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक खतरनाक है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से निवेदन करती है कि देश की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डालने वाली इस परियोजना को कार्यान्वित होने से अविलंब रोके तथा देश की श्रद्धा के केन्द्र राम सेतु को संरक्षित कर ऐतिहासिक स्मारक घोषित करें। अभाविप संपूर्ण संत समाज उन राजनैतिक दलों, सामाजिक सगंठनों, प्रचार माध्यमों तथा नागरिकों का अभिनंदन करती है जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा हेतु जनजागरण करते हुए आंदोलन जारी रखा है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से मांग करती है कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर समझौतावादी नीति को त्याग कर स्पष्ट एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय हित में काम करे। साथ ही देश भर के युवाओं एवं आमजन से अपील करती है कि वह सरकार की राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर समझौतावादी निति का विरोध करते हुए व्यापक जन जागरण अभियान चलाये। ■

प्रस्ताव ६

1857 के स्वातंत्र्य समर की 150वीं वर्षगांठ

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद 1857 की 150वीं वर्षगांठ के पावन पर्व पर इस महासंग्राम में शहीद हुतात्माओं के पुण्यस्मरण के साथ उन्हें विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करती है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने देश की आम जनता ने सदा ही विदेशी आक्रान्ताओं का प्रतिकार किया है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भी देश में अलग–अलग स्थानों पर लगातार संघर्ष होता रहा है।

1857 का योजनाबद्ध स्वाधीनता संग्राम भी इस सतत् संघर्ष की कडी है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस योजनाबद्ध संग्राम को सैनिक विद्रोह, गदर, सामंतशाही बताने का प्रयास के रूप में प्रस्थापित करने का प्रयास किया और वर्तमान वामपंथियों ने इसको वर्ग संघर्ष का जामा पहनाने की कोशिश की, लेकिन इस संग्राम को वास्तविक तथ्यों के साथ स्वातंत्र्य महासागर के रूप में प्रस्थापित करने का श्रेय स्वातंत्र्य वीर सावरकर को जाता है। अपनी मातृभूमि पर अवैध कब्जा जमाऐं विदेशियों के विरूद्ध उठ खडे होना विद्रोह कैसे हो सकता है यह तो स्वधर्म की रक्षा एवं स्वराज्य की स्थापना करने के लिए संघर्ष था। यदि चरबी युक्त कारतूस के कारण यह सैनिक

विद्रोह होता तो क्यों गवर्नर जनरल के कारतूस वापसी को घोषणा के बाद भी यह स्वाधीनता संग्राम चलता आ रहा क्यों इस में सैनिकों के अलावा भी विभिन्न रियासतों एवं आम जनता ने स्वाधीनता हेतु संघर्ष किया, इस समर में तीन लाख से अधिक लोगों ने बलिदान दिया। अकेले अवध क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार हुतात्माओं में से एक लाख तो सामान्य लोग ही थे।

कुछ इतिहासकारों ने इसे केवल उत्तर भारत के कुछ हिस्सों का ही संघर्ष बताया जबकि यह राष्ट्रव्यापी महासंग्राम था जो कि मेरठ, दिल्ली, झाँसी, बितूर, शिवपुरी, काल्पी, मुम्बई, बंगाल, मद्रास आदि स्थानों में हुआ। मुम्बई में 1213, बंगाल में 1994, मद्रास में 1044 सैनिकों के कोर्ट मार्शल हुए। यह सिद्ध करता है कि 1857 का संग्राम राष्ट्रव्यापी ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वाधीनता संग्राम था जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ, हजारों गांवों को तहस–नहस कर दिया गया, अनेक किले खण्डहर बना दिये गये सम्पूर्ण देश ही एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। अमाविप का मत है कि यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित राष्ट्रवादी स्वातंत्रय समर था। इस संघर्ष में रजवाडों से लेकर आम आदमी, साधु–सन्तों, मौलवियो सहित हिन्दू–मुस्लिम सभी ने मिलकर लड़ाई लडी थी। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति अपनाते हुए उन सभी तौर तरीके का उपयोग किया, जिससे भारत में राष्ट्रीयता का भाव कमजोर हा जाये, परिणाम स्वरूप 10 साल बाद भारत का विभाजन हो गया। आज हमें फिर इस तरह के चल रहे अराष्ट्रवादी प्रयत्नों से सावधान रहने की आवष्यकता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों से मांग करती है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठयक्रमों में इस संघर्ष को जिस प्रकार से गलत ढंग से प्रस्तुत करके पढाया जा रहा है, ऐसे प्रस्तुतिकरण को हटाया जाये और देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले सभी क्रांतिकारियों को उचित सम्मान के साथ युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने के लिये कदम उठाये जाये। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद पुरजोर मांग करती है कि अंग्रेजों ने जो अमानवीय अत्याचार 1857 के क्रांतिकारियों और भारत की आम जनता पर किये उसके लिये ब्रिटिष सरकार भारत की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे।

1857 के मूलप्रेरक – प्रथम शहीद, मंगल पाण्डे, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झाँसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खाँ, झलकारी बाई, दक्षिण के नरगुंद बाबा साहेब, गोंद राजा शंकर शाह जैसे अनेक क्रांतिकारियों का पुण्य स्मरण आने वाली पीढ़ियों में बना रहे। इस लिये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद 1857 के स्वातंत्रय संग्रम की 150वी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं का आवाहन करती है, देश गुलामी की मानसिकता के चिन्हों को हटाकर इसे महापुरूषों को सम्मानपूर्वक स्थापित करते हुए स्वाभिमान संपन्न राष्ट्र खडा करने की दिशा में अग्रसर हो और परिश्रम से अपने देश को शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाये साथ ही देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा के समक्ष खतरा बनी शक्तियों को परास्त करें।1 ■

Justice done on India's first terror encounter

The verdict given by TADA Judge P.D. Kode on the 1993 Mumbai serial bomb blasts should be etched in gold. After 12 years of hearing the 1993 blasts case, Kode's verdict seeks to be a harsh deterrent against terrorist acts.The on-going endless debates and arguments on the legalities had been closely watched even by the international community and foreign media.

While nursing a fractured shoulder, Kode sentenced 12 key conspirators to death and 20 others to life imprisonment from among the 100 convicted in the case. But it was the six-year jail term for Sanjay Dutt, undisputedly the most high-profile figure in the case, that reinforced the public's faith that all are equal before law.The trial almost consumed the man behind the judge though. On July 24, when Kode sentenced the three Mahim bombers to death, it was his father's death anniversary. But the judge presided over the court proceedings just as he had done when his father died in 2000. In fact, the two-week break when he fractured his shoulder on June 24 was the first time he took leave.

Shrouded in Z-plus security, he is bound to his New Marine Lines home except when he goes to court and his annual Shirdi pilgrimage. Kode's verdict helped to prove that India is not a soft state. Over 257 innocent lives were lost in the blasts in Mumbai.

देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल

आजादी की साठवीं सालगिरह पर निर्वाचन मंडल ने देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं की प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक महिला, प्रतिभा देवीसिंह पाटील को चुनकर देश की आधी आबादी का सम्मान किया है। तकरीबन आठ बरस के राजनीतिक वनवास के बाद 2004 में राजस्थान की राज्यपाल बनकर लौटी। महाराष्ट्र के छोटे से शहर जलगांव की रहने वाली पाटिल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की। 1962 में वह पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनी गईं। उसके बाद लगातार 1985 तक वह विधायक चुनी जाती रहीं। इस दौरान राज्य में उन्होंने उपमंत्री, मंत्री और नेता विपक्ष की भूमिका निभाई।

प्रारम्भ में जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की तलाश हो रही थी, उस वक्त दूर–दूर तक पाटिल का नाम कहीं नहीं था। लंबे समय से उनकी गिनती गांधी–नेहरू परिवार में निष्ठा रखने वालों में की जाती रही है। उनकी इसी सच्ची निष्ठा ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव की दौर में शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, कर्ण सिंह, अर्जुन सिंह और मोती लाल वोरा जैसे दिग्गजों को पिछे छोड़कर आगे लाकर खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में 19 दिसम्बर 1934 को जन्मी पाटिल ने जलगांव के एमजे कालेज से एमए किया। बाद में मुम्बई लॉ कालेज से विधि की डिग्री हासिल की। डा. देवी सिंह शेखावत से 7 जुलाई 1965 को उनका विवाह हुआ। उनका एक पुत्र राजेन्द्र सिंह और एक पुत्री ज्योति है। उनकी खेलों में भी रुचि है। वे अपने कॉलेज जीवन में टेबल टेनिस चैम्पियन रहीं हैं और इंटर कालेज प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 1991 में वे अमरावती से पहली बार लोक सभा के लिए चुनकर आईं और अगले पांच वर्षों तक दोनों सदनों में विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करती रहीं।

वर्ष 1996 के बाद पाटिल राजनीतिक गलियारों से गायब सी हो गई। किसने सोचा था कि सिर पर पल्लू रखने वाली और माथे पर बिंदिया लगाने वाली, देखने में सीधी–सादी घरेलू महिला पाटील एक दिन भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। ■

Hamid Ansari is Vice-President

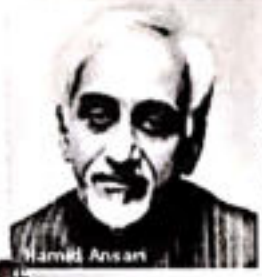

Former diplomat and academic Shri Mohammad Hamid Ansari, elected India's vice president.A familiar face in the diplomatic circles, 70-year-old former envoy Ansari will be perhaps busy with preparing himself for this new role.

Coming from a family of freedom fighters, Ansari's familiarity with politics, in fact, began much before he joined the Indian Foreign Service.

He hails from Ghazipur in Uttar Pradesh, though he was born in Kolkata in 1937.After completing his post graduation in Political Science, Ansari joined the Indian Foreign Service in 1961. He was Permanent Representative of India to the United Nations, High Commissioner to Australia and Ambassador to the United Arab Emirates, Afghanistan, Iran and Saudi Arabia.

In May 2000, Ansari became the vice chancellor of the Aligarh Muslim University which he had graduated from.

He is a scholar of West Asian affairs and has written extensively on the subject. He has also edited the book, *Iran Today: Twenty Five Years After the Islamic Revolution.*

मुलाकात

डा. रामनरेश सिंह
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभाविप)

राष्ट्र की सुरक्षा और शिक्षा के व्यवसायीकरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं, जो अत्यंत बुनियादी एवं महत्वपूर्ण विषय हैं लेकिन केंद्र सरकार की समझौतावादी नीतियों से ये दोनों विषय भी हाशिये पर आते जा रहे हैं प्रस्तुत है इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष *डा. रामनरेश सिंह* से *"उमाशंकर मिश्र"* द्वारा की गई बातचीत के प्रमुख अंश –

विद्यार्थी परिषद् की वेबसाइट पर सवाल उठाया गया है कि क्या बांग्लादेश; भारत का, पाकिस्तान से भी बड़ा शत्रु है? ऐसा किस लिहाज से कहा गया है?

शत्रु तो दोनों हैं, बड़ा और छोटा क्या। लेकिन बांग्लादेश ने भारत के जनसंख्या अनुपात को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। घुसपैठ इसका सबसे बड़ा जरिया है। हाल ही विद्यार्थी परिषद् के 64 कार्यकर्ताओं की एक टीम ने 1074 किलोमीटर भारत–बांग्लादेश सीमा का सर्वेक्षण किया और पाया कि बांग्लादेशी 'नोमेन्स लैण्ड' क्षेत्र में भी बेघड़क रह रहे हैं। यही नहीं वे सीमा के 200 गज भीतर तक घुस आये हैं। इसके अलावा भारत के भीतर भी असम के 42 विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी वर्चस्व होता जा रहा है। ऐसे कई इलाके पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हैं। इस तरह बांग्लादेश भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, भूभाग और जनसांख्यकीय अनुकूलन के लिहाज से खतरा बनता जा रहा है। यही नहीं बांग्लादेश को कुल विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत हिस्सा भारत से पशु तस्करी से प्राप्त होता है। सरकार वर्षों से इस बात की उपेक्षा करती आ रही है और आज भी कर रही है। विद्यार्थी परिषद् की टीम में बांग्लादेश सीमा पर बसे समाज में राष्ट्रीय भावना के प्रसार का कार्य किया है, जिससे जनभागीदारी के माध्यम से समस्या के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके। उल्लेखनीय है कि – चीन और वियतनाम युद्ध के समय जब वियतनाम की सेना पीछे हटने लगी तो वहां की जनता ने आगे आकर मोर्चा थाम लिया। अंततः चीनियों को वापस पीछे जाना पड़ा। 1983 में बने आईएमडीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में निरस्त कर दिया जिससे विद्यार्थी परिषद् के सर्वेक्षण की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है।

अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर देश में बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। आखिर इस देश में अल्पसंख्यक कौन है?

यह बात आज तक ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं हो सकी है कि अल्पसंख्यक आखिर किसे कहा जाए! इसके लिए भारत सरकार के स्पष्ट नियम हैं। यह काम सरकार, संविधान और संसद मिलकर तय करेंगी कि इस देश में अल्संख्यक कौन है। लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति में इस कद्र ग्रस्त है कि कोई निर्णायक फैसला हो सकेगा इसकी संभावना बहुत कम ही जान पड़ती है।

कुछ समय पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी ने कहा था कि विश्वविद्यालयों को सरकारी मदद की आस नहीं देखनी चाहिए और लाभ के उद्देश्य से काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर?

उनका यह कहना इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से सरकारें शिक्षा जैसे बुनियादी विषय से अपना पल्ला झाड़ने पर तुली हुई हैं। सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से हाथ खींच कर खुद को सामाजिक कल्याण की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। इससे पिछड़े एवं गरीब तबके लोगों के हितों को ठेस पहुंचेगी और गरीब छात्र शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जाएंगे। विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध काफी

चर्चा हुई है। शिक्षा व्यवसायीकरण का विषय कतई नहीं हो सकती।

हाल ही में केरल और भुवनेश्वर में विद्यार्थी परिषद् कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

केरल और भुवनेश्वर में परिषद् कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जिस तरह से पुलिसिया कार्यवाही की गई वह निंदनीय है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने, विरोध प्रकट करने और मांग प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार है। विरोध प्रदर्शन भी सरकार को चेताने के लिए ही किया जाता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार कोई सकारात्मक कार्यवाही करने की बजाय इस तरह के बर्बर कृत्यों पर उतर आती है।

फिलहाल शिक्षा और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी किस किस्म की चुनौतियां देश के सामने हैं?

शिक्षा का व्यावसायीकरण फिलहाल देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था और युवा पीढ़ी के भविष्य पर एक काले बादल की तरह छाया हुआ है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। जो इस अधिकार को प्राप्त कर पाने में अक्षम है, कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतों की व्यवस्था करे। लेकिन यहां तो सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को विदेशी हाथों में सौंपने को तुली हुई है। इससे न केवल गरीबों के हित उपेक्षित होंगे बल्कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार और ऐतिहासिक उपलब्धियां भी विदेशी शिक्षा संस्थानों के भारत में आने पर हाशिये पर चली जाएंगी। इसके अलावा जिस तरह से केंद्र सरकार अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि राष्ट्र की संप्रभुता को सरकार अमेरिका के हाथों गिरवी रखने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं कठपुतली बने हुए हैं, ऐसे में कोई सकारात्मक पहल हो सकेगी इसकी संभावना अत्यंत क्षीण जान पड़ती है। अंततः एक ही बात कही जा सकती है कि यह पूरी तरह से असफल सरकार है। ■

TRIBUTE

Shri Chandra Shekhar

Former Prime Minister Chandra Shekhar who held center-stage of Indian politics for almost four decades with his unflinching commitment to socialism and strong distaste for personality politics passed away at a New Delhi hospital on 8th July 2007.

The only Indian elevated as Prime Minister without having previously held an official post, 80-year-old Chandra Shekhar died after battling "multiple mycloma" (cancer of plasma cell) for three months. Two sons survive him.

During the course of his tumultuous but distinguished career, Chandrashekhar often ruffled political feathers and took the courage to defy former Prime Minister Indira Gandhi during his days in the Congress and earned the sobriquet of a "young turk". But he maintained friends across parties and ideologies. Chandrashekhar was a disciple of Acharya Narendra Dev and eight times MP from Ballia.

With Chandra Shekhar's death, the country has lost a leader who knew the pulse of the masses and was a strong pillar of Indian democracy.

Former Prime Minister AB Vajpayee described him as a "friend of friends who lived in politics on his own terms and had a natural tendency to raise his voice against injustice.

यौन शिक्षा : विरोध के प्रखर स्वर

यौन शिक्षा पाठ्यक्रम को स्कूलों में लागू किए जाने की बात को लेकर, इसके दूरगामी परिणामों की उपेक्षा करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी हठ पर अड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस विवादास्पद पाठ्यक्रम के लागू हो जाने से न केवल हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का स्तम्भ धराशायी हो जाएगा, बल्कि आने वाली नस्लें भी इसके प्रभाव से संक्रमित हो जाएंगी। केंद्र सरकार को छोड़कर इस बात को समाज के विभिन्न वर्गों ने गहराई से समझा है और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। जिसे *"उमाशंकर मिश्र"* ने एक रिपोर्ट के रूप में पिरोया है

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट के अध्यक्ष फिरोज पटेल ने कुछ समय पूर्व कहा था कि "देश में नैतिक शिक्षा पर जोर देने के बजाय यूनीसेफ और कंडोम–कंट्रासेप्टिव बनाने वाली पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव से यौन शिक्षा कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है, जो देश को एक बाजार के रूप में देखते हैं। पटेल का दावा था कि यूनीसेफ और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों ने पश्चिमी देशों की जरूरतों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यौन शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया है। जो भारतीय परिदृश्य में पूरी तरह अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि "यह शिक्षा सामाजिक मार्यादा को पूरी तरह से धवस्त कर देगी। इस शिक्षा से भारतीय संस्कृति, बड़ों का सम्मान व गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता भी खतरे में पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े इतिहासकार देवेन्द्रस्वरूप के मुताबिक "यौन शिक्षा केवल बच्चों को काम वासना की ओर धकेलने वाली चीज है। यह उन्हें संयम का पाठ सिखलाने वाली शिक्षा कदापि नहीं है।" भारतीय सभ्यता में यौन विषयों को अत्यंत गोपनीय एवं मर्यादा के दायरे में रखा गया है। इस संवेदनशील विषय को जिस तरह से चौराहे पर सरेआम उछाला जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो असमंजस की अंधी गलियों में कैद हो जाए।

किशोरों को यौन शिक्षा नहीं, जीवन कौशल शिक्षा देंगे, यह कहना है; राजस्थान की मुख्यमंत्री वसंधरा राजे सिंधिया का। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि प्रमुख राज्यों के बाद राजस्थान सरकार ने भी अब यौन शिक्षा से पल्ला झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री राजे ने मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह से पत्र लिखकर मांग की है कि स्कूलों में यौन शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को पढ़ाए जाने की अनुमती न दें, क्योंकि 9वीं एवं 10वीं के छात्र किशोरावस्था की दहलीज पर होते हैं और इस प्रकार की शिक्षा का उन पर निश्चय ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। अभी तक कुल नौ राज्यों ने यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने से इंकार कर दिया है। इससे इस मुद्दे पर सर्वसम्मति के केन्द्र सरकार के प्रयासों को झटका लगा है। अब तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ भी इस श्रंखला में शामिल हो चुके हैं। इन राज्यों ने यौन शिक्षा से संबंधित पुस्तक को पढ़ाने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया है,अथवा पाठ्यक्रम में से यौन शिक्षा सामग्री को हटा दिया है। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के राज्यों ने यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का जबरदस्त विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार को भी भारी विरोध के समक्ष झुकना पड़ा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश पर राज्यों के केंद्रीय विद्यालयों में यह पाठ्यक्रम शुरु हो रहा है। लेकिन जिन राज्यों ने इसे लागू करने से इन्कार कर दिया, वहां पर राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विद्यालयों के बीच टकराव होना तय है। एड्स नियंत्रण के नाम पर कामसूत्र पढ़ाने की इस तैयारी की जहां एक तबका पुरजोर हिमायत कर रहा है, वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि शिक्षक वर्ग के साथ अभिभावक और किसी हद तक खुद बच्चे भी इस दलील को हजम नहीं कर पा रहे हैं। पाठ्यक्रम में जिस तरह से शिक्षा दी गई है, उसे पढ़ाने में शिक्षक भी संकोच अनुभव कर रहे हैं।

इस संबंध में शिक्षकों को यूनीसेफ की ओर से प्रशिक्षण भी दिया गया तथा पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों के संबंध में किताबें भी दी गई। इनमें एक किताब जीवन के लिए शिक्षा जिसे शिक्षकों और विद्यार्थियों हेतु पारीवारिक स्वास्थय और जीवन कलाओं की शिक्षा की गाइड बताया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् एवं प्रशिक्षण संस्थान , नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन और यूनीसेफ ने मिलकर इसे तैयार किया है। कक्षा नौ और दस में इसे सामाजिक विज्ञान का विषय बनाया गया है। जबकि कक्षा 11 वीं और 12 वीं में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का पाठ बना दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत से पूर्व ब्रिटेन जैसे देशों में बहुत पहले ही यौन शिक्षा कार्यक्रम शुरु किये जा चुके हैं। हमारा देश अपने आंचल में तमाम संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को समेटे हुए है। लेकिन ब्रिटेन जैसे देशों की कौन सी ऐसी संस्कृति है, जिसके कारण वहां शिक्षक खुलकर यौन विषयों से जुड़े छात्रों के सवालों पर जवाब देने में अटपटापन महसूस करते हैं। आखिर भारत जैसी कौन सी गुरु शिष्य परंपरा है, जिसके कारण ब्रिटेन के शिक्षक सहज नहीं अनुभव कर पाते हैं? जी हां ये बातें भारत की नहीं अपितु ब्रिटेन जैसे विकसित देश की हैं, जहां काफी पहले ही यौन शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम लागू किए जा चुके हैं। प्रतिष्ठित बी.बी.सी. हिन्दी डॉट कॉम पोर्टल पर साफ तौर से बताया गया है कि बच्चे यौन संबंधों के बारे में ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं, जिसका शिक्षक कोई जवाब ही नहीं दे पाते। इस तरह की स्थिति के चलते ब्रिटेन में एक समय तो यौन शिक्षा कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया था। ब्रिटेन ऐसा देश है जहां किशोर लड़कियों के मां बनने के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। इसी बात को आधार बना कर वहां "एक्जेटेर विश्वविद्यालय" ने कुछ समय पूर्व किशोरों में यौन शिक्षा के बारे में एक कार्यक्रम शुरु किया था। ब्रिटेन की एक शिक्षिका के मुताबिक इस यौन शिक्षा कार्यक्रम से किशोरों में कोई जागरूकता नहीं बनती, बल्कि उन्हें यह समझाना मुश्किल होता है कि 16साल से पहले कम उम्र में यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है। उनकी मुख्य चिंता यही रहती है कि किशोरों को यौन शिक्षा के बारे में अटपटे सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं? इस तरह का असमंजस तो एक पाश्चात्य देश की शिक्षिका को हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा चुका है कि वहां किशोर लड़कियों के मां बनने के मामले सबसे अधिक मिलते हैं। जो उस देश में भोंडेपन एवं संस्कृतिविहीन होने की बात को दर्शाता है। लेकिन इतने पर भी एक ऐसे देश की शिक्षिका अपने छात्रों से इस विषय पर बात करने में असहज महसूस करती है। ऐसे में एक भारतीय शिक्षक की परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे वह छात्रों के समक्ष अपनी बात रख सकेगा? और यदि रखेगा तो फिर हजारों वर्षों की उस गुरु शिष्य परंपरा का क्या होगा जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और जिसके दम पर हम विश्वगुरु कहलाने की क्षमता हासिल कर सके थे। क्या वह कायम रह पाएगी? इन सवालों पर यदि आप सोचेंगे तो आप मानसिक झंझावात से कांप उठेंगे।

बीबीसी के हवाले से बताया गया है कि–ब्रिटेन की शिक्षिका लिन्डा ब्राइन एक उदाहरण पेश करती हैं जिसमें एक चौदह साल की लड़की पूछती है कि "वीर्य का स्वाद कैसा होता है।" एक अन्य सवाल में एक पंद्रह वर्षीय एक लड़के का उदाहरण देते हुए लिण्डा ने बताया है कि वह पूछता है– क्या पुरुष और पुरुष के बीच यौन संबंध बनाए जा सकते हैं? लिन्डा खुद से ही सवाल करती हैं कि आखिर इस उम्र के बच्चे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं।

लिन्डा ब्राइन एक रोमन कैथोलिक ईसाई हैं और दो बच्चों की मां हैं। वे एक कुशल शिक्षिका हैं और कहती हैं कि किशोरों को यौन शिक्षा देते समय वे भी सहज नहीं रह पाती हैं।

इस तरह के सवाल यदि भारतीय स्कूलों कक्षाओं में पूछे जाएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी आखिर किस ओर जाएगी ये सोचने का समय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह को नहीं है। आखिर देश की सभ्यता एवं संस्कृति यौन शिक्षा के नाम पर विदेशियों के हाथों बेचकर वे किस तरह के मानव संसाधन का विकास करने का स्वप्न संजोए बैठे हैं? इस तरह के प्रश्नों की भले ही केंद्र सरकार ने अवहेलना की हो लेकिन अभिभावकों एवं शिक्षको ने भी इसके विरोध में आवाजें उठानी शुरु कर दी हैं। राजनीति और दलाली चमकाने के लिए राजनीतिज्ञों को देश की भावी पीढ़ी के भविष्य एवं हजारो सालों की परंपरा, संस्कृति से खिलवाड़ के लिए क्या खुली छूट दे देनी चाहिए? इस बारे में अभिभावकों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों इत्यादि को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। तभी सरकार को सुनाई देगा, क्योंकि यह सरकार ऊंचा सुनती है। ■

पश्चिम से आयातित सेक्स एजुकेशन का बादल आया पूरब के सूरज को निगलने

केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्री सेक्स एजुकेशन को लेकर जिस तरह से अपने दाव चल रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि वह भारतीय संस्कारों का कबाड़ा करके पश्चिम का कूड़ा यहां आयात करना चाहते हैं। हाल ही में 'सेक्स एजुकेशन के विरोध' में वरिष्ठ चिन्तकों, शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों,सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ। जिसके बाद देश भर में यौन शिक्षा के विरोध में एक माहौल तैयार हुआ। यह एक बहस का विषय बना है। इसी कार्यक्रम पर आधारित है आशुतोष कुमार 'अंशु' की संक्षिप्त रिपोर्ट–

वरिष्ठ शिक्षाविद, सम्माननीय राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एस लाहोटी और जैन, सिक्ख, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों ने 'सेक्स एजुकेशन (यौन शिक्षा) के विरोध में' 14 जुलाई को आयोजित विशाल सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्री और सीबीएसई को चेतावनी दी कि छात्रों में जागरूकता लाने के नाम पर सेक्स एजुकेशन की आड़ में गंदी राजनीति न करें।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता जैन संत विजयरत्न सुन्दर सुरीश्वर कर रहे थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा– हम रोडरा एजुकेशन को लेकर सीबीएसई और एनसीईआरटी के विरोध में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विषय हम संसद में उठाएंगे और इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, जिससे सरकार यह भयावह और आत्महत्या करने वाला कदम न उठाए।

श्री सुरीश्वर ने सेक्स एजुकेशन की भयावहता को समझाते हुए कहा कि यदि यह शिक्षा लागू हो जाती है तो हमें उसके बाद देश के स्कूलों को निठारी गांव के रूप में देखने को तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं फिर आम हो जाएंगी और देश के कोने–कोने से ऐसी खबरें आएंगी। उन्होंने सेक्स एजुकेशन का विरोध करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं नहीं चाहता, हमारे देश के स्कूल ब्रिटेन की तरह गर्भपात के केन्द्र बने। फ्रांस की तरह छोटी उम्र की बच्चियों को गर्भ निरोध की गोलियां खिलानी पड़े, बिन ब्याही मां बनने का चलन अमेरिका की तरह यहां बढ़े और न्यूजीलैन्ड की तरह छात्र– छात्राओं का शिक्षक द्वारा यहां यौन शोषण हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एड्स के मरीज सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति का मान नहीं रखा।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों ने अपने यहां सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगाई हुई है। पूर्व केन्द्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा– सरकार भारतीय गुरू–शिष्य परंपरा को भुलाकर पश्चिमी देशों के गुरू–शिष्य के बीच यौन संबंध की नीति को भारत में आयात करना चाहती है। श्री जोशी ने कहा कि यह सेक्स एजुकेशन नहीं है, यह पश्चिमी देशो का अपना

कंडोम नाम का उत्पाद बेचने का एक माध्यम है। पूर्व न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी ने कहा कि यदि दुनियां एक पति, एक पत्नी के भारतीय परंपरा को अपनाए तो एड्स नाम की बीमारी का अपने आप दुनियां से खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि 1998 तक वहां 64.8 फीसदी लड़कियां 18 साल से कम उम्र में गर्भवती हो गई थीं। यह आंकड़ा 4 फीसदी प्रति वर्ष की दर हर साल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में यह आंकड़ा 83 फीसदी का है और कनाडा में हालत और भी बुरी है। पश्चिमी देशों में समलैंगिकता और रक्त संबंधियों में यौन संबंध का चलन भी बढ़ता जा रहा है। क्या हम कभी चाहेंगे कि यह सब कुछ भारत में भी हो?

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक जार्ज फर्नांडिस ने सेक्स एजुकेशन के राष्ट्रव्यापी विरोध पर जोड़ दिया। शिक्षा बचाओ आन्दोलन के संयोजक दीनानाथ बत्रा ने साफ शब्दों में कहा कि आन्दोलन इस देश में कभी सेक्स एजुकेशन की इजाजत नहीं दे सकता। भारत के पूर्व राजदूत ओ.पी गुप्ता ने कहा कि बहुत सारे अभिभावकों ने यौन शिक्षा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत शिक्षकों पर मुकदमा किया है।

इस विशाल सम्मेलन के माध्यम से सेक्स एजुकेशन के पीछे केन्द्रिय नेतृत्व की जो साजिश है, उससे लोग–बाग वाकिफ हुए। वास्तव में सेक्स एजुकेशन के नाम पर यह बहुराष्ट्रीय कंडोम कंपनियों के लिए बाजार खड़ा करने की कवायद मात्र है। आर्कबिशप, मुम्बई की प्रतिनिधि बनकर आई डा. थाइलमा ने कहा कि जिस कंडोम बाजार बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी सौ फीसदी एचआईवी से सुरक्षा नहीं देता। अनैच्छिक गर्व से भी यह सौ फीसदी मुक्ति नहीं देता।

सम्मेलन में विद्वानों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। अब यह उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन से जो एक बहस खड़ी हुई है, उसका खात्मा 'सेक्स एजुकेशन' के त्रिजन्न के विदाई के बाद ही होगा। इस अवसर पर शिवसेना के विधायक श्री राजेन्द्र पटाणी, सेंट ज़ेवियर स्कूल, मुम्बई की प्रिंसिपल प्रतिमा नैथानी, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डा. कपिल कपूर, जमायत–ए–इस्लाम हिन्द के असिस्टेन्ट सेक्रेटरी इंतज़ार नईम, डा. तारा सिंह और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह–संगठन मंत्री श्री अतुल कोठारी जैसे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ■

Ram Sethu protection movement gathers momentum

The streets of Madurai are eternal witness to fight for justice. Valiant Kannagi could bring the erring Pandiya king to book by her fearless struggle here. On July 22, under an overcast sky threatening to cause a downpour, the junction of North and West Maasi Streets of Madurai (Tamil Nadu) was filled with determined Hindu men and women for a struggle to protect Ram Sethu built by Shri Ram.

The huge rally of 40,000 people, including 8,000 women, was organised by the Rameshwaram Ram Sethu Protection Movement (RRSPM) to chart a course of action so that the just demand of the Hindus is heeded. Three resolutions passed at the meeting appealed for:

- Declaration of Ram Sethu as an ancient national monument under the Acient Monuments Act of 1904 by the government.
- Observing fast in public on the ensuing Aadi (Ashad) Amavasya day (August 12) to pray to god to effect a change in the attitude of state and central governments in the matter of Ram Sethu.
- Celebrating Raksha Bandhan this year (August 28) as "Ram Sethu Raksha Bandhan" to create awareness among all, about Ram Sethu protection campaign.

The dignitaries who had expressed solidarity with the Ram Sethu protection movement in the messages they sent include: Mata Amritanandamayee Devi, Mahant Nrityagopal Das and the holy Aadheenakarthas of Dharmapuram and Thiruvavaduthurai.About 40 youngsters carried a "flame of justice" from Rameshwaram to Madurai. The numerous participants returned home with a resolve to muster support in a big way to the mighty task of protecting the Ram Sethu. ■

व्यवस्था को धूल–धुसरित होने से बचाने के लिए युवाओं को क्या कदम उठाने होंगे

परिचर्चा के उक्त विषय में मूलतः तीन शब्द प्रमुख हैं। व्यवस्था, युवा, और क़दम। इन्हीं तीन शब्दों के आस–पास विचारों और चिन्तन का दायरा खिंचा हुआ है। जहाँ तक प्रश्न व्यवस्था का है उसमें केवल प्रशासन और राजनीति तक ही विषय को सीमित नहीं किया जा सकता। व्यवस्था में पर्यावरण, अर्थ, समाज, कानून, शिक्षा, न्याय और जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को गणित किया जा सकता है। युवा के विषय में आयु की सीमाओं को तोड़ कर सक्रियता और सोच को आधार बनाया जाना चाहिए। तथा कदम को तात्पर्य केवल भाषणबाज़ी और धरने–रैलियों तक सीमित न होकर ज़िम्मेदारी लेने की पहल तक विस्तृत होना आवश्यक है। परिचर्चा के माध्यम से युवाओं की राय को प्रस्तुत किया है, *"चिराग जैन"* ने।

मनीष मक्कड़, अभियंता

बहुत से आर्थिक और सामाजिक कारणों से आज का युवा समाज और व्यवस्था की समस्याओं से दूर भागना चाहता है। 'सब चलता है' और 'एक अकेले के करने से क्या होगा' जैसे वाक्य उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं।समस्याओं को सुलझाने के लिए अंततः युवाओं को आगे आना ही होगा।

सर्वप्रथम तो पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु सतर्क होना हमारी वरीयता होनी चाहिए। दूसरे अपनी कार्यों के प्रति ज़िम्मेदारी लेना सीखना होगा। और क्विक मनी और ग्लैमर के मोह से बाहर आकर राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होकर व्यवस्था का हिस्सा बनना होगा।

दिशा जैन, आईबीएम

कॅरियरस्टिक होने का यह क़तई मतलब नहीं है कि समाज और देश की समस्याओं से मुँह मोड़ लिया जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम केवल राजनेताओं को गालियां देकर या व्यवस्था को कोस कर अपने आपको महान समझ बैठें। हम जिस समाज के अंग हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। युवावर्ग यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं के जंजाल से बाहर निकल कर पल भर के लिए इन कर्तव्यों की ओर देख ले तो फिर षायद व्यवस्था को कोसने की बजाय समाधान ढूंढने और उन पर अमल करने का प्रयास कर सके, जो उसे खुद ही करना होगा।

मुक्ता, एमटेक, आईआईआईटी

बुराई इसलिए नहीं फैलती कि बुरे लोग ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए फैलती है कि जब बुराई सड़क पर घटित हो रही होती है तो अच्छे लोग दरवाज़े बन्द कर लेते हैं। यही व्यवस्था की ख़ामियों का मूल कारण भी है। दरअसल हमारी सामाजिक अकर्मण्यता और स्वार्थी भावनाओं के कारण समाज और व्यवस्था के स्वामी ऐसे लोग बन बैठे हैं जिनका सरोकार राष्ट्रहित से न होकर महज ओछे स्वार्थों से है। ऐसे में हम उन लोगों को पूरी तरह दोषी इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि उनके हाथों में सत्ता देने का अपराध अंततः हम से ही हुआ है सो हमें ही इसको वापस लेने के प्रयास भी करने होंगे।

शम्भू शिखर, कवि

अनिश्चितताओं के इस युग में जब बाज़ारवाद हर जगह हावी हो गया है, ऐसे में युवाओं का अवसरवादी हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसका यह तो अर्थ नहीं निकलता कि अपनी मूल प्रवृत्ति को त्याग दिया जाए। हमारी मूल प्रकृति है सामाजिक होना। मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के प्रति उसके कुछ दायित्व हैं। इन्हीं दायित्वों का निर्वाह युवाओं को करना चाहिए। राजनीति को कीचड़ कह देना या विदेषों की ग्लैमरस ज़िन्दगी की ओर नदीदों की तरह देखना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह पलायनवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। हमें पलायन की यह प्रवृत्ति त्याग कर सक्रिय रूप से राश्ट्र निर्माण की ओर ध्यान देना होगा। और इतना

न भी कर सकें तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जब कोई बच्चा राष्ट्र और समाज की बात करे तो उसे बच्चा कहकर उसका उपहास न किया जाए। क्योंकि देश की चिंता करना बच्चों का खेल नहीं।

सुशील कुमार, रेलवे कर्मचारी

वही वृक्ष किसी लता को सहारा दे सकता है जिसका अपना आधार मजबूत हो। इसलिए यदि देश का युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में वह रहे उसमें जी लगाकर मेहनत करे और स्वयं को सि(करके दिखाए। शिक्षा, इंजीनियरिंग, अर्थ, विज्ञान, चिकित्सा या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में जब वह अपनी स्थापना कर लेगा तो देश के विषय में और व्यवस्था के विषय में खुलकर सोच पाएगा और सक्रिय रूप से हिस्सा भी ले पाएगा। अनेक फिल्मी हस्तियां और औद्योगिक घराने इस तथ्य के प्रमाण हैं।

परिचर्चा

भारत में अल्पसंख्यक कौन ?

इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। इस परिचर्चा में पाठकों के विचार आमंत्रित है। अधिक से अधिक 500 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ 31 सितम्बर तक प्रेषित करें। प्राप्त उत्तर सितम्बर– अक्तूबर अंक में प्रकाशित किये जायेंगे

सम्पादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति
136, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001

In Kerala, comrades' own Tantric university

Marx may have called religion the opium of the people, but comrades ruling Kerala are set to ensure that it thrives. The Left Democratic Front government is seriously thinking of starting a full-fledged Tantric university in Kerala. The only similar university in the country is the Dalai Lama's Gyuto Tantric University in Himachal Pradesh. "Spiritual and ritualistic practices in our temples have been deteriorating. This is turning people off," said senior CPM leader and Minister for Temple Affairs G Sudhakaran, maintaining that a Tantric university has been found "necessary" to shore up the state's waning spiritual inclinations.

He said top Hindutva scholars, Vedic exponents, and spiritual gurus will be roped in as faculty. The university will run courses for aspiring priests, besides running continuing education programmes for those already working in temples. However, the government doesn't plan to insist that all priests be required to pass the courses — for that would mean fiddling with the touchy area of the traditional and largely hierarchical offices of priests and tantris.

Also, the government doesn't want the Tantric university yoked to the University Grants Commission. Sudhakaran says it will be run by a trust set up under the Devaswom Board, which manages temple affairs in Kerala and is under government control.

Incidentally, the late CPM ideologue E M S Namboothiripad had opposed the setting up of the Sri Sankaracharya Sanskrit University in Kalady, saying Sanskrit was a dead language, and such a university would only "aid and abet Hindu communalism." He had said that Sankaracharya's Advaita philosophy was outdated and caused India to remain backward. But after he died in the 1990s, the Left government then in power set up a chair in Namboothiripad's name in the same university. ■

Yuva Vikas Kendra
- the vision of a new dimension -

Students Experience in Inter State Living (SEIL), a project of ABVP is a unique example of success story in bringing about the much desired national integration. Through organising tours of young students from far off border areas – particularly the North Eastern region of India to other parts of this vast nation, the SEIL has provided them direct experience of unity and integrity of Bharat. Thousands of students who participated in this programme not merely visited the places but also stayed with the local host families which gave them an enduring experience of life, finding a home away from home. Thus the SEIL motto-" Unity in Diversity is India's Specialty"-becomes a practical and successful experiment of defeating the distance –both physical and psychological. That is the contribution of SEIL, a registered trust, since its inception in 1966.The mission SEIL has since added many dimensions to its activities.

With this background, SEIL has embarked upon a novel project" Yuva Vikas Kendra" at Guwahati, for the development of North East youth and also for involving them in the development of the region.

Yuva Vikas Kendra- The vision of a new dimension.

The rich picturesque and strategic north east region of India has a significant presence of dynamic youth segment. North East region of Bharat is endowed with abundant natural resources, rich galaxy of cultural traditions and life styles of a silent but intelligent, smiling and creative people. But unfortunately this region is dogged with variety of complex problems viz.insurgency,violence,drug

trafficking,AIDS,unemployment,exploitation of innocent people etc. apart from recurring natural calamities.

The situation calls for an urgent and effective action plan for channelising the youth power into constructive, nation-building activities focusing the north east.

Precisely to answer this call,SEIL has launched Yuva Vikas Kendra(YVK)at Guwahati on 27 Feb 2004.

Vision of YVK

With the vision to create a permanent centre which will be window and mirror of the youth from the North East India, SEIL decided to set up Yuva Vikas Kendra (YVK) at Guwahati.

This centre aims at providing training and leadership development programmes with a focus on Economic Development by promoting Youth development & Youth for development.

YVK has completed its 2 years of working and it has kept up its promise of being a centre for study, research, interaction, creativity, dynamism, communication and training by organizing

ectures, Workshop, Study circles, Field visits nd Certificate courses.

ctivities – Range of Projects

cademic Projects.

- Certificate Courses in various skills and trades.
- Training, Orientation, opinion making and awareness programmes.
- Seminars, workshops, lecture on socio economic issues.
- Research and study projects; Documentation.
- Conducting sector wise short duration courses on career opportunities in the North East and out of region.
- Conducting interview, technique camps, preparatory camps for IAS, Banking service or Military service recruitment.

Reference Centre

- A library of general as well as tourist info books on life and issues of North East.
- Publication of booklets, monographs and occasional study papers.

Cultural Projects.

- Cultural Experience and National Integration tours.
- Culture appreciation and Eco-protection camps.
- Exhibitions and cultural festivals.
- Promotion of the folk arts and martial art forms.
- Museum: Conservation of cultural heritage of North East.

Other Dimensions

- Personality Development courses/camps.
- Entrepreneurship motivation courses and camps.
- Entrepreneurship development courses and camps.
- Vocational training.
- Holistic training for community development.
- Career guidance.
- Community awareness and service.

Seminars and Study Circles

1. Flood Situation In Assam.
2. BODO Culture and their History.
3. Rural Industrialisation in Assam.
4. Is L P G right path to VISION 2020.

Certificate Courses (3 Months Duration)

1. Sanskrit Sambashan Sibir.
2. Course in Spoken English.
3. Course in basics of Computer.

YVK SCIENCE FESTIVAL 2005

- About 350 Persons (Students, Parents and Teachers) visited science festival in two days.
- Visit to 51 School and colleges of Kamrup District.
- Exhibition of 18 Models (Senior Group-3, JuniorGroup-15).
- 11 Schools participated in Science Quiz.
- More than 40 Students availed the facility of Career Counseling and Guidance.
- Mobile Model Van was also the one of the main attraction for participants as well as local Students and youth.
- Lecture on: Preparation for Competitive Exams (Science stream)

YVK AT A GLANCE 04-06

Activity	*No. of Events*	*No. of Participants*
P D P	3	129
Camps	4	534
Seminars	4	207
Competitions	6	156
CertificateCourse	3	70
Lecture	16	894
Foundation Day	4	210
Workshops	2	98

छात्र संघ चुनाव – चुनौतियां एवं दिशा

"राज्यस्तरीय परिसंवाद"

महाराष्ट्र: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेश आयोजित छात्र संघ चुनाव – चुनौतियाँ एवं दिशा यह राज्यस्तरीय परिसंवाद दि 15 जुलाई 2007 को मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। 12 साल बाद पुनः शुरू होने वाले छात्र संघ चुनाव से जुडे हुए कई अहम मुद्दों पर विचार , चर्चा इस परिसंवाद में हुए। इस चुनाव से जुड़े कई प्रश्नों पर; जैसे चुनाव की क्या पद्धति होगी,इसकी पात्रता क्या रहेगी,आचार संहिता क्या होगी, इस पर शैक्षिक क्षेत्र में एक संभ्रमित वातावरण हैं। इस चुनाव से संबंधित सभी प्रश्नों की स्पष्टता और इस निर्णय के अमल के लिए विद्यमान विभिन्न विचारों को एक मंच पर लाने का प्रयास अभाविप ने किया।

महाराष्ट्र राज्य के असिस्टेंट ॲडव्होकेट जनरल ॲड.अशुतोष कुंभकोणी ने इस परिसंवाद का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री श्री.परमेश्वर हासबे ने अपने प्रास्ताविक में इस परिसंवाद का आयोजन का हेतु और स्वरूप स्पष्ट किया। श्री.राजेश पांडे, सिनेट सदस्य,उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,ने बीजभाषण किया। अपने उद्घाटन भाषण में ॲड. कुंभकोणी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की व्याप्ती एंव मर्यादा का उल्लेख किया।

इस परिसंवाद के दुसरे सत्र में महाराष्ट्र प्रांत विद्यापीठ विकास मंच के निमंत्रक प्रा.धनंजय कुलकर्णी से प्रतिनिधियों ने खुली बातचीत की।

परिसंवाद के तीसरे सत्र में छात्रसंघ चुनाव – छात्र संगठनों की भुमिका इस विषय पर महाराष्ट्र के प्रमुख छात्र संगठनों के नेताओंने अपने विचार प्रस्तुत किया।

परिसंवाद के समापन सत्र में महाराष्ट्र में इस चुनाव पर विचार करने के लिये गठित समिती के सदस्य आमदार श्री.जितेंद्र आव्हाड ने अपनी भुमिका रखी।

दिन भर के परिसंवाद का समापन एवं संकलन प्रा. मिलिंद मराठे ने किया।15 जिलों से 108 प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में हिस्सा लिया। वंदेमातरम् गान से इस परिसंवाद का समापन हुआ।

■

Gujarat

Signature campaign to protest remark by Panikkar at MS University.

Vadodara, July 11: Akhil Bharatiya Vidhyarti Parishad (ABVP) and University Youth Group launched an agitation against Prof Shivji Panikkar's comments on Hindu Bhajans being played in Sayajibaug, by initiating a varsity-wide signature campaign on MS University campus.

ABVP leaders said that, what Prof Panikkar said was unforgivable and are not only demanding his rustication from the varsity, but want him exiled from Vadodara as well, for hurting people's sentiments.ABVP leaders said that the signature campaign commenced at the Faculty of Arts and Commerce , and is set to cover all the faculties in MSU. "We received around 4,000 signatures from Arts and Commerce faculties," they said. They added that they planned to get at least 15,000 signatures and submit the memorandum to the MSU authorities.

Also University Youth Group led by Arts faculty general secretary Rupesh Prajapati said, "Prof Panikkar's cartoon was made with a gun and was take out in the faculty. Around 700 signatures were collected by them and plans to have 8,000 signature." Prajapati said Panikkar has abused the value of teachers by making such statement.

ABVP members also spoke to students about the entire issue in an effort to garner more support for their cause. According to ABVP, some students knew of the issue from media reports, while others had to be told of the incident, after which they pledged their support. "The signature campaign is only the beginning, the protests may intensify in a few days time," ABVP said. At a panel discussion on higher education and university autonomy , Panikkar had made

controversial statements referring to Hindu bhajans being played at Sayajibaug every morning and that he was forced to listen to the songs as he went for morning walk there. ABVP leaders strongly condemned his statements.

Kerala

olice lathicharge ABVP activists in Kasargode,Kerala

KASARGOD: Police lathicharged about a ndred ABVP activists who stormed the Murali kund auditorium here where the Bus Owners' sociation was holding its convention on ednesday.

The ABVP activists, who were protesting ainst the bus operators' decision to stop travel ncession for students, stormed the auditorium er smashing the gate.The ABVP activists nained in the hall for half an hour shouting gans. The meeting resumed after the ABVP ivists were removed by the police. Later, the sociation leaders told media persons that the dents' travel concession should be revised mediately. The association state president A K bdullah said the concession would be stopped om July 15.

Meanwhile, the ABVP said in a statement hat the police lathicharged its activists without ny provocation. It said the agitators were taking ut a peaceful march to the venue of the onvention.

Karnataka

ABVP demands removal of Karnataka Women's University V C

Bangalore: Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) activists staged a protest seeking removal of Karnataka State Women's University Vice-Chancellor Syeda Akhtar, who is facing charges of financial irregularities.

Addressing the protesters, ABVP's Former All-India general secretary K.N. Raghunandan, said the Government was delaying removal of the Vice-Chancellor, who has been faulted by the S.R. Venkatesh Murthy Commission that looked into financial irregularities. "The Government is dismissing the finding on a technical ground and is contemplating to set up another inquiry commission to look into the issue," he said.

Mr. Raghunandan said the Government was a mute spectator to Ms. Akhtar's gross misuse of official power and disobeying the orders of the State Government. Recently, she went ahead with a Syndicate meeting disregarding the order of Principal Secretary, Department of Higher Education. He charged that Ms. Akhtar had violated the norms laid down by the University Grants Commission and Karnataka University Act on recruitment.

Tejaswini Sriramesh, MP, said the delay on the part of State Government in replacing Ms. Akhtar was affecting the image of the university.

The State Government should replace Ms. Akhtar with an able administrator. She would raise the issue with Chief Minister H.D. Kumaraswamy and Higher Education Minister D.H. Shankaramurthy. She would apprise Congress president Sonia Gandhi and seek her intervention, the MP said.

Orissa

Police lathi charged ABVP activists in Bhubaneswar

BHUBANESWAR: Police lathi charged the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) activists,who were protesting the commercialisation and irregularities in higher education in the state.

Police swung into action when the ABVP activists led by its state secretary Nirmal Sarangi broke the police barricades and marched towards the State Aassembly shouting slogans in favour of their demands.Among other things, the student

organisation demanded an immediate cessation of corruption and privatisation of plus two education.

Protests were also against the government's permission to open private university without enacting law, allotment of 8000 acres of land to vedanta to set up a university on Puri-Konark sea beach, and shifting of the central educational institutions like Indian institute of management, Indian Institute of Science and Indian Institute of Technology from Orissa to other places.

Setting up of a central and tribal university in the state were their other demands.

ABVP organised a signature campaign against female foeticide in Bhubaneswar

Bhubaneswar: As the Nayagarh female foeticide case continued to hit headlines, as many as 14 foetuses were found lying behind a private clinic in the Forest Park locality of the city. Although it was not immediately known if they were female foetuses, hundreds of people gathered on the spot to have a glance of the plastic containers with uteruses and foetuses inside. "The sex of the foetuses will be known only after examination," Chief Medical Officer of the government-run Capital Hospital Loknath Acharyasaid.Bhubaneswar Diagnostic and Polyclinic from where the foetuses were recovered is located about 300 metres away from Chief Minister Naveen Patnaik's house.

Large scale female foeticide in the State had come to light when a school student spotted some polythene bags containing seven female foetuses near Nayagarh town on July 14. Subsequently, Nayagarh police recovered a large quantity of infant body parts from inside a pit on the outskirts of the town. Activists of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad organised a signature campaign against female foeticide and infanticide by putting up a large banner near Rama Devi Women's College of the city. Hundreds of students put their signature on the banner to protest against female foeticide in the State.

Central U P

यौन शिक्षा के विरोध में उतरी अभाविप.

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा यौन शिक्षा पाठ्यक्रम के लागू करते ही झांसी में भी विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। अभा.वि.प. के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में जिला मुख्यालय पर पर प्रदर्शन कर यौन शिक्षा को न लागू करने की मांग की है। सह जिला संयोजक रोहित गोठनकर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध दर्ज करवाया। छात्रों ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में जागरूकता की बजाय मानसिक विकृति पैदा होगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यौन शिक्षा के नाम पर पुस्तकों में जो पढ़ाया जाना है, उसे धारा 377 के तहत अपराध माना गया है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि देश में योग एवं प्राणायाम जैसी अनेक विधाएं हैं जिनसे विद्यार्थी काफी कुछ सीख सकते हैं। बाद में प्रतिनिधि मंडल ने अपर जिलाधिकारी शमीम अहमद खान को ज्ञापन सौंपा।

Andhra Pradesh

Commercial varsities: Andhra CM draws flak

The reported advice of Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy to the universities to become 'money earners' for their sustenance without looking for government funds has drawn flak at the two-day state executive meeting of ABVP, which concluded in Tirupati on July 2. The meet in its resolution on 'education' described the Chief Minister's advice to the varsities as 'irresponsible' and said that it betrayed the government's intention to escape from its fundamental duty of providing education to its people. The meet regretted that the entire education sector in the State was caught 'irretrievably' under the clutches of the private and corporate educational institutions and cited in this connection the recent remarks of the Supreme Court that 90 per cent of the degree colleges in the State lack even the basic infrastructure. ■

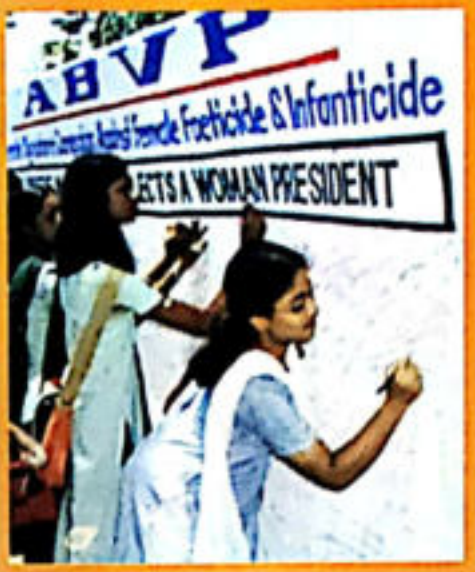

Signature campaign against female foeticide in Bhubaneswar

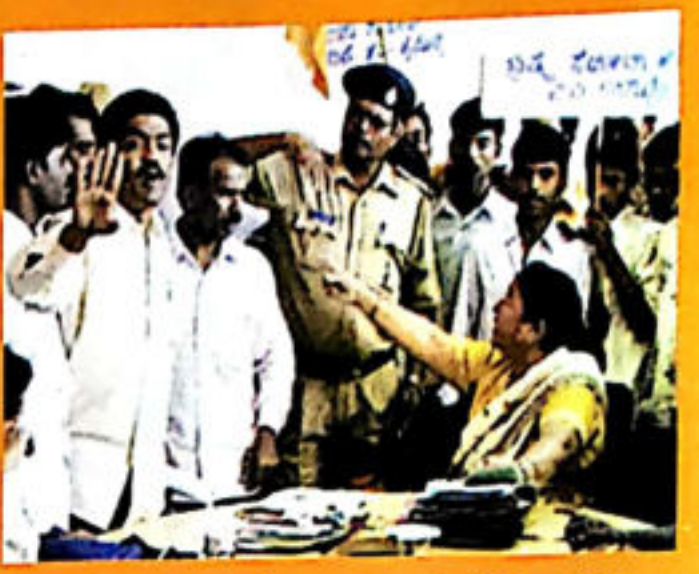

Agitation demanding removal of Karnataka Women's University V C

School students protest against negligent driving which claimed a student's life at Hyderabad.

Police lathicharging ABVP activists agitating against Muslim quota in Andhra Pradesh

Glorious Moments

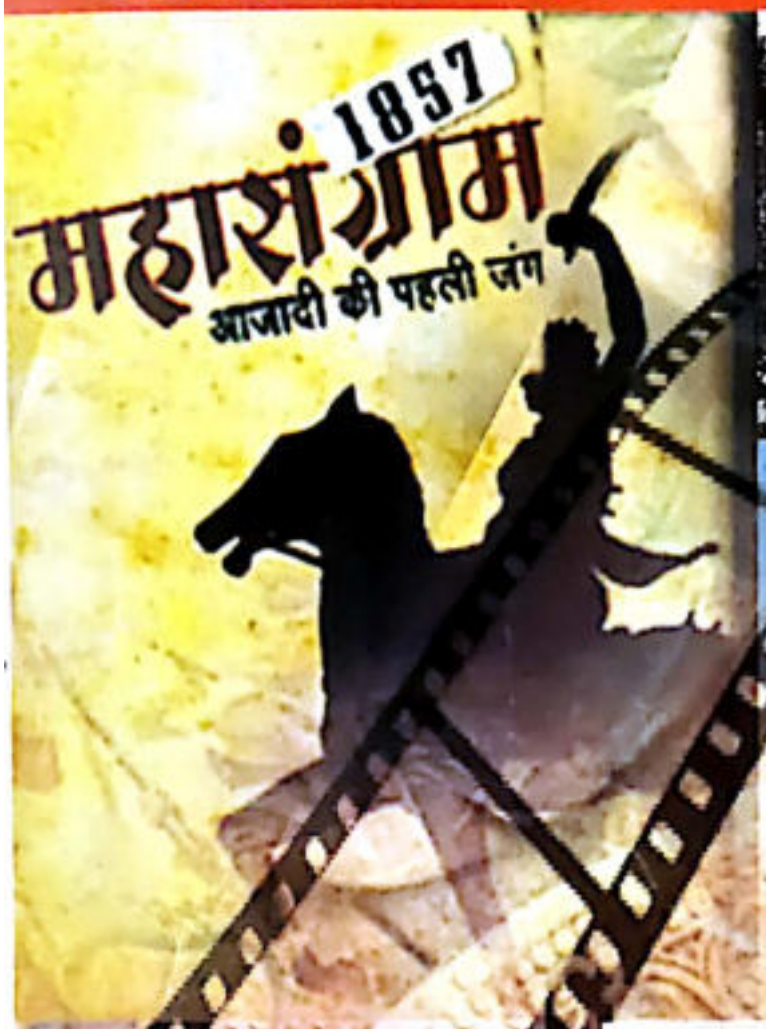

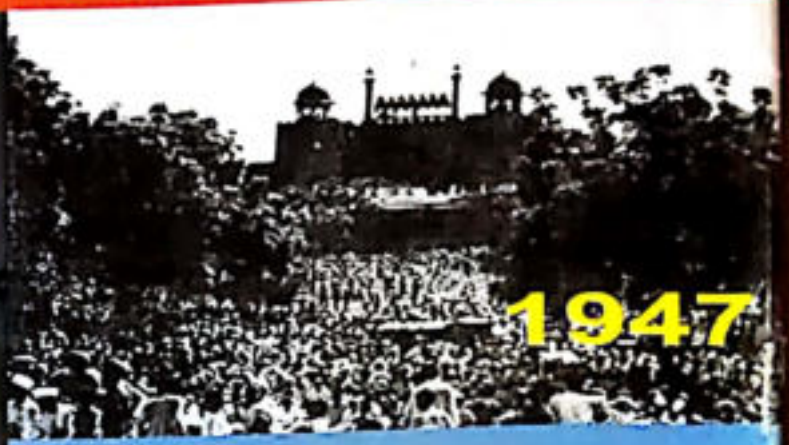

Vision 2020

building a strong India by 2020